● वर्ष-5
● अंक-300
रायपुर, रविवार
02 अगस्त 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> बाढ़ प्रभावित परिवारों के ...

संसद में अब भी टकराव जारी

गृहमंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़ा विपक्ष; सरकार ने बनाई नई रणनीति

नई दिल्ली। संसद में छात्रों के खिलाफ पुलिस के सख्त बलप्रयोग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। छात्र आंदोलन के विरोध मार्च के दौरान जेन-जी के खिलाफ लाठीचार्ज तथा पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहा विपक्ष अपने हमले के सियासी तेवर नरम करने के लिए तैयार नहीं। तो छात्रों की मांग पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कर चुका सरकार भी इस मुद्दे पर विपक्ष को कोई राजनीतिक मौका नहीं देने को लेकर सतर्क है। पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा के तत्काल बाद ही विपक्ष ने गृहमंत्री के सदन में आकर बयान देने से लेकर उनके इस्तीफे की मांग को हवा देने का अपना दांव चल दिया।

विपक्षी दलों के इस दांव को भांप कर सरकार ने भी दोनो सदनों में हंगामे के बीच बिना चर्चा के ही विधेयकों को पारित कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जबकि विपक्ष ने भी गृहमंत्री पर हमले की अपनी रणनीति में लचीलापन लाने के अभी कोई संकेत नहीं दिए हैं। सरकार को इस मुद्दे पर दबाव में बनाए रखने की विशेष रूप से कांग्रेस की रणनीति का संकेत

शनिवार को राहुल गांधी की तमिलनाडु यात्रा के दौरान नीट पेपर लीक से हताश होकर आत्महत्या करने वाले कुछ छात्रों के परिजनों से चर्चा के दौरान भी मिला।

जेन-जी के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता के लिए गृहमंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग कर चुके नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा संसद में विपक्षी पार्टियों के तेवर नहीं बदलने का साफ संकेत दिया।

कांग्रेस नेता ने छात्र आंदोलन के दौरान जेन-जी द्वारा अपशब्दों के इस्तेमाल पर उन्हें माफ करने के प्रधानमंत्री के शुक्रवार रात जारी बयान को ही उन्हीं पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। चेन्नई में पीड़ित छात्रों के परिजनों संग अपने मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता के आंसू, उनका बिलखना, इससे बड़ा कोई दु:ख नहीं होता।

भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली के बारे में कई सवाल

ये एक गम उनके साथ हमेशा जिंदा रहेगा। और साथ ही रह जाते हैं इस टूटी और भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली के बारे में कई सवाल। पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी एक पल में बर्बाद। हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो खुद बेईमान है। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की ये हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक से छीन लिए गए? जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए।संसद में गतिरोध कायम रहने की आशंका इसलिए भी है कि सत्तापक्ष और विपक्ष ही नहीं बल्कि स्पीकर ओम बिरला की तरफ से इसका हल निकालने की अभी तक कोई पहल नहीं हुई है।

राष्ट्रपति ने एंटी-पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है. जिसमें लोक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामलों में आरोपियों के जल्दी सजा दिलाने के लिए हर राज्य में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और सजा बढ़ाने का प्रावधान है.शुक्रवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन में, कानून मंत्रालय ने संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की जानकारी दी. एंटी-पेपर लीक कानून में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक इस हफ्ते की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था.नया कानून लागू होने के बाद, पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने के अंदर पूरी होनी है. कानून के अनुसार, पेपर लीक या परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाने वालों को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।

बॉक्सिंग में पहली बार 5 गोल्ड

प्रीति, जैस्मिन, साक्षी, प्रिया और अरुंधति चैंपियन बनीं; अब तक 34 मेडल

ग्लासगो। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार एक ही गेम्स में 5 बॉक्सिंग गोल्ड जीत लिए। शनिवार को प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास और अरुंधति चौधरी चैंपियन बनीं। वहीं, लवलीना बोरगेहन को सिल्वर से संतोष करना पड़ा।पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा ने भी गोल्ड जीता। मेडल टैली में भारत 11 गोल्ड, 15 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज सहित कुल 34 मेडल हो गए और टीम चौथे स्थान में पहुंच गई है।अरुंधति चौधरी ने 70किलो में इंग्लैंड की कैंथले रीड को 5-0 से हराया। अंतिम राउंड के शुरुआती 30 सेकेंड में रेफरी ने दोनों मुक्केबाजों को खेल की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा। अरुंधति की प्रतिद्वंद्वी रीड को मुकाबले में वापसी के लिए आक्रामक होना था, लेकिन भारतीय मुक्केबाज ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया।

महिलाओं के 60 किलो फाइनल मुकाबले में भारत की प्रिया घंघास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कड़े मुकाबले में उन्होंने मिले जुले फैसले में 4-1 से जीत हासिल की।प्रिया ने मुकाबले की तेज शुरुआत की, लेकिन उनकी प्रतिद्वंद्वी अल-अहमदियेह ने भी कुछ सटीक पंच लगाकर जोरदार जवाब दिया। फाइनल राउंड में दोनों मुक्केबाजों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। प्रिया थकी हुई नजर आ रही थीं, लेकिन उन्होंने लगातार आक्रामक रुख बनाए रखा और दमदार पंच लगाती रहीं।महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भारत की साक्षी चौधरी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और यूनानिमस डिसीजन 5-0 से जीत हासिल की।साक्षी ने मुकाबले के दौरान बेहतरीन रणनीति अपनाई। उन्होंने बाएं हाथ से प्रतिद्वंद्वी के पंचों को रोका और दाएं हाथ से लगातार सटीक जवाबी हमले किए। उनके कई पंच सीधे प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर लगे, जिससे मुकाबले में उनकी पकड़ मजबूत होती गई।महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में भारत की उन्नति शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोस्टर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्नति ने मुकाबला महज 1 मिनट 7 सेकेंड में इप्पोन के जरिए जीत लिया।

मुख्यमंत्री साय ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से की सौजन्य भेंट

रायपुर-नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन से सौजन्य भेंट की। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ के विकास, सुशासन, संगठनात्मक समन्वय तथा जनहित से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और केंद्र-राज्य समन्वय से आगे बढ़ रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की।

आतंकियों ने नाम पूछकर छत्तीसगढ़ के मजदूरों को गोली मारी, वहीं हुआ अंतिम संस्कार

छग सरकार देगी 20-20 लाख, उमर सरकार 10 लाख के साथ जिला प्रशासन की ओर से की गई 6-6 लाख की तत्काल सहायता घोषित

रायपुर-नई दिल्ली। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को पहलगाम जैसा हमला हुआ। आतंकवादियों ने ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के नाम पूछे। फिर छत्तीसगढ़ के दो हिंदुओं को समूह से अलग करके उनका धर्म पूछा और फिर गोली मार दी। हमले में एक मजदूर की मौके पर और दूसरे मजदूर की अस्पताल में मौत हो गई। मारे गए युवक की पहचान 24 साल के दीपक रात्रे और 28 साल के भूपेंद्र के रूप में हुई है। मृतकों के परिजन उनका अंतिम संस्कार गृहग्राम में लाकर करना चाह रहे थे लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से दोनों युवकों का अंतिम संस्कार कुलग्राम में किया गया। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के शैडो संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। घाटी में महज 10 दिनों के भीतर टारगेट किलिंग की यह दूसरी बड़ी घटना है। इस आतंकी हमले को लेकर प्रदेश में चारों तरफ शोक की लहर है। लोगों में भारी आक्रोश है और वे आतंकियों के इस कायराना कृत्य की कड़ी निंदा कर रहे है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपये और उमर सरकार ने 10 लाख रुपये के साथ जिला प्रशासन के द्वारा 6-6 लाख रुपये की तत्काल सहायता राशि घोषित की गई।अधिकारियों के अनुसार, हमला कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम में हुआ। इस दौरान 3-4 राउंड फायर किए गए। आतंकियों ने हमले से पहले रेकी करके ये इलाका चुना था। घटना के समय वहां कई प्रवासी मजदूर मौजूद थे, लेकिन हिंदू सिर्फ यही दोनों थे। आतंकी हमले की खबर के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। गाडियों की चेकिंग की जा रही है। वहीं पुलिस की गाडियां आतंकियों की तलाश में जुट गई हैं। जानकारी के अनुसार, दीपक रात्रे सक्ती जिले के मालखरौदा विकासखंड की ग्राम पंचायत बुंदेली के निवासी थे। करीब एक वर्ष पहले वे अपने पिता उमाशंकर रात्रे और परिवार के साथ मजदूरी करने जम्मू-कश्मीर गए थे।

एसटीएफ ने जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी को दबोचा निशाने पर थे सीएम शुभेंदु

कोलकाता। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में उसकी एक महिला साथी को भी पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी मोहम्मद हमीम मंडल को पुरबा बर्धमान जिले से शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। जबकि हमीम की कथित महिला मित्र और सहयोगी अर्पिता सरकार को भी शुक्रवार रात को हिरासत में लिया गया। इस दौरा आरोपियों के पास से ब्रिटेन और मैक्सिको के अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड मिले हैं, जिनका इस्तेमाल विदेशी हैंडलर्स से बात करने के लिए किया जाता था।एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा के अनुसार, आरोपी हमीम मंडल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहा था। उसका एक बड़ा प्लान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रखना और उन जगहों की जानकारी जुटाना था जहाँ वे सुरक्षा घेरे से बाहर होते हैं।आरोपी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर तोड़फोड़ और हिंसा फैलाने की योजना बनाई थी।

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक परीक्षाओं के बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी

नयी दिल्ली। सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष त्वरित अदालत स्थापित करने और दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस विधेयक को पारित किया था। अब प्रश्नपत्र लीक के मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। कानून के अनुसार, प्रश्नपत्र लीक कराने या परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास की सजा तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, संगठित अपराध से जुड़े मामलों में संशोधित कानून के तहत कम से कम सात वर्ष के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार

पुणे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पुणे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। तिलक स्मारक ट्रस्ट के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अजीत डोभाल को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। 81 वर्षीय अजीत डोभाल ने मिजोरम, सिक्किम, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने इस्लामाबाद और लंदन स्थित भारतीय मिशनों में राजनयिक भूमिका भी निभाई है। डोभाल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वह भारत-चीन सीमा वार्ता में भारत के विशेष प्रतिनिधि भी रहे हैं। डोकलाम गतिरोध को सुलझाने के लिए हुए कूटनीतिक प्रयासों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तिलक स्मारक ट्रस्ट ने बताया कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में हुई थी।

आठ अगस्त को प्रयागराज आएंगे राहुल गांधी

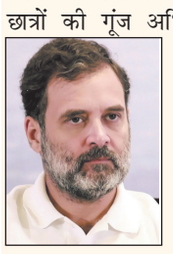

प्रयागराज। नीट और सीबीएसई घटनाक्रम को लेकर फिर देशभर कि राजनीति गर्म होने वाली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 17 जून को कोटा से छात्रों की गूंज अभियान का पहले चरण की शुरुआत करने के बाद दूसरा चरण 17 जुलाई को देहरादून में हुआ। इसके बाद तीसरा चरण प्रयागराज में 8 अगस्त को होना तय हो गया है। जबकि 9 अगस्त को दिल्ली में विशाल छात्र रैली के साथ इस चरण का समापन होना था। पार्टी प्रवक्ता हसीब अहमद के बताया कि प्रयाग में आयोजित होने वाली छात्रों कि गूंज कार्यक्रम में रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत, छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयों के माहौल और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बताया कि राहुल के छात्र संवाद में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी सहित अन्य जिलों के छात्र शामिल होंगे।

दिल्ली में लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च, महिलाओं ने भरा फॉर्म

नईदिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार ने अपना एक और चुनावी वादा पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लॉन्च कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चार महिलाओं को उनके आवेदन के बाद प्रमाणपत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना डेढ़ साल के संकल्प के बाद शुरू की गई है। उन्होंने इस पहल पर खुशी व्यक्त की। दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत लक्ष्मी नगर और गीता कॉलोनी से हुई है। पोर्टल शनिवार से ही आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया है। अब तक करीब 500 महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपने फॉर्म भर दिए हैं। यह योजना महिलाओं के स्वावलंबन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। अब तक दिल्ली लक्ष्मी योजना में कुल 10830 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

राम मंदिर चंदा नाटक पर पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर

नईदिल्ली। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ़ शुक्रवार, 31 जुलाई को संसद परिसर में राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर किए गए प्रदर्शन के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत याचिकाकर्ता सूर्य मैथिल ने जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। मीडिया से बात करते हुए सूर्य मैथिल ने कहा कि पप्पू यादव ने भगवा का अपमान किया और संसद के बाहर उनके किए गए ड्रामे को राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद और इंडिया गठबंधन के अन्य सांसदों का समर्थन मिला। इसमें पप्पू यादव ने भगवान राम लला विराजमान की तस्वीर तक अपने पैरों के नीचे रख दी... इससे सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शुक्रवार को पप्पू यादव ने संसद में राम मंदिर के कथित चंदा घोटाले पर चर्चा की विपक्ष की मांग को उजागर करने के लिए भगवा कपड़े पहने पुजारी के वेश में और हाथ में चंदा पेटी लेकर प्रदर्शन किया था। लोगों का ध्यान खींचने के लिए पूर्णिया के सांसद ने हिंदू संत का वेश धारण किया और विरोध-प्रदर्शन के तहत चंदा इकट्ठा करने के लिए एक प्रतीकात्मक चंदा पेटी साथ रखी।

जंतर-मंतर छात्र आंदोलन

दिल्ली पुलिस बल का कमजोर होना अच्छा संकेत नहीं

मीरा च । बोरवणकर

हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन ने एक बार फिर पुलिस की भूमिका और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जायज मांगों को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' नामक छात्र संगठन ने यह आंदोलन किया था। कुछ जगहों पर, खासकर दिल्ली में, आंदोलन से निपटने में पुलिस का रवैया उतना संयमित और संवेदनशील नहीं था, जितनी उससे अपेक्षा थी। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में छात्रों के आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हुए और पुलिस ने भी पूरे संयम के साथ स्थिति को संभाला।

भारत में पुलिस व्यवस्था और पूरी नौकरशाही नागरिकों के बजाय राजनीतिक नेतृत्व के प्रति अधिक जवाबदेह होती जा रही है। यह स्थिति दिन-ब-दिन और साफ दिखाई देने लगी है। किसी आपात स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए और उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, इसका फैसला भी अक्सर राजनीतिक स्तर पर होता है।

असल में मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को हालात का आकलन करके खुद फैसला लेने की आजादी होनी चाहिए। साथ ही, अपने फैसलों के लिए उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। दुर्भाग्य से नागरिकों के प्रति जवाबदेही की भावना इतनी कमजोर पड़ गई है कि राजनीतिक दबाव से दूर रहकर पूरी पेशेवर ईमानदारी से काम करने वाला अधिकारी आज सामान्य नहीं, बल्कि 'अपवाद' माना जाने लगा है।राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भला-बुरा कहा और उसके व्यवहार को लेकर शिकायतें भी कीं। लेकिन हकीकत यह थी कि कई पुलिसकर्मियों को अपने स्तर पर फैसला लेने की आजादी ही नहीं थी। बेखौफ अपनी बात कहने वाली और सत्ता से सीधे सवाल करने वाली नई पीढ़ी से निपटने के लिए हमारी पारंपरिक पुलिस व्यवस्था तैयार नहीं थी।

इस आंदोलन से निपटने के लिए ज्यादा संवेदनशीलता, समझदारी और सूझबूझ की जरूरत थी। दिल्ली के राजनीतिक नेतृत्व ने समय रहते हालात की गंभीरता को नहीं समझा और आखिरकार संगठित युवाओं के दृढ़ इरादों के आगे उसे पीछे हटना पड़ा। यह सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की ही नहीं, बल्कि पुलिस और राजनीतिक खुफिया तंत्र की भी बड़ी चूक थी।प्रश्नपत्र लीक होने की लगातार घटनाओं और बढ़ती बेरोजगारी से 'जेन-जी' में जो गहरा गुस्सा पनप रहा था, उसका वे समय रहते सही अंदाजा नहीं लगा सके। जनता के मन की बात और उसके बीच पनप रहे असंतोष को सही ढंग से समझने के लिए पुलिस के खुफिया तंत्र को और मजबूत बनाने की जरूरत है।जानकारी जुटाने के पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ सोशल मीडिया के रुझानों, वहां बन रही जनधारणा और लोगों की भावनाओं को समझना आज के तकनीक के दौर में बेहद जरूरी हो गया है। इसी तकनीक की मदद से शांतिपूर्ण आंदोलनों में घुसकर हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।साथ ही, तनावपूर्ण स्थितियों में संयम खोकर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वाले अधिकारियों को भी व्यवस्था से बाहर करना जरूरी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रशिक्षण में नियमित मॉक ड्रिल, रोल-प्ले और वास्तविक घटनाओं के अध्ययन को हर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में अनिवार्य किया जाना चाहिए। कई राज्यों में सेवाकालीन प्रशिक्षण और 'रिफ्रेशर कोर्स' लगभग बंद हो चुके हैं।इन्हें नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। किसी भी संवेदनशील जगह पर तैनाती से पहले पुलिसकर्मियों को वहां के हालात के बारे में पूरी जानकारी देना बेहद जरूरी है। उन्हें यह भी साफ तौर पर बताया जाना चाहिए कि बल का प्रयोग कब और किस हद तक करना है। इसी तरह हर बड़ी घटना के बाद व्यवस्थित ढंग से उसकी समीक्षा हो और उससे सबक लेने की संस्कृति विकसित की जाए।आज हर नागरिक के हाथ में मोबाइल कैमरा है। इससे किसी भी घटना को देखने और पेश करने का पूरा तरीका बदल गया है। पुलिस व्यवस्था को भी इस बदलते दौर के मुताबिक खुद को ढालना होगा। इसके साथ ही प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने में अब और देरी नहीं की जा सकती।पुलिस बल को कानून-व्यवस्था और अपराध की जांच से जुड़ी दो अलग-अलग शाखाओं में बांटने से दोनों अपने-अपने दायित्वों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान दे सकेंगी। इससे कानून-व्यवस्था से जुड़ी खुफिया सूचनाएं जुटाने का तंत्र मजबूत होगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस की कार्रवाई भी अधिक प्रभावी हो सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस बल को अधिक स्वायत्तता देने की जरूरत पर भी स्पष्ट रूप से जोर दिया था। लेकिन तबादले और नियुक्तियों के लिए राजनीतिक नेतृत्व पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता अधिकारियों की पेशेवर निर्णय लेने की क्षमता पर बुरा असर डालती है।

कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा कावड़ियों के लिए बनाए जा रहे विश्राम स्थलों का किया गया निरीक्षण

कलेक्टर ने मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करने, कांवड़ स्टैंड लगाने के दिए निर्देश

कवर्धा। सावन माह में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए बेमेतरा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इसी क्रम में कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आज बूढ़ा महादेव मंदिर परिसर से लेकर रायपुर मार्ग स्थित रानीसागर, बिरकोना और दशरंगपुर में बनाए गए विश्राम स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने तथा किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बूढ़ा महादेव मंदिर परिसर के समीप निर्माणाधीन डोम का अवलोकन किया और कांवड़ियों के लिए बेहतर विश्राम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने रानीसागर में बनाए गए कांवड़ स्टैंड का निरीक्षण किया तथा बिरकोना के पंचायत भवन में कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए पृथक शौचालय, स्वच्छ पेयजल तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने दशरंगपुर स्थित विश्राम स्थल का निरीक्षण कर वहां भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कहा कि कबीरधाम जिले के साथ-साथ बेमेतरा एवं अन्य जिलों से आने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि पदयात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक एवं धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र भोरमदेव मंदिर और पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर, कवर्धा में सावन माह के दौरान कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा पदयात्रा कर भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस दौरान कबीरधाम सहित बेमेतरा एवं अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों पर विश्राम, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम वातावरण में अपनी यात्रा पूर्ण कर सकें।

कोरबा में सरकारी कार्यालयों पर बिजली विभाग का 97 करोड़ रुपए बकाया

कोरबा। जिले में सरकारी विभागों का करोड़ों का बिजली बिल भुगतान पेंडिंग हैं। विभागों पर बिजली विभाग का कुल बकाया 97 करोड़ पहुंच गया है। शासकीय दफ्तरों पर अब बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाने की बात कही है। वहीं विभाग प्रीपेड मीटर लगाने की भी तैयारी कर रहा है। शासकीय दफ्तरों का कुल बकाया बिजली बिल बढ़कर 97.135 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। विभागों के शासकीय होने के कारण स्थानीय अधिकारी इन पर खुलकर दबाव नहीं बना पाते, जिससे यह बकाया लगातार बढ़ता रहता है। बिजली विभाग ने इस स्थिति से निपटने के लिए जिले में चल रहे स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान में तेजी लाई है। अब शासकीय कार्यालयों में पोस्टपेड (इस्तेमाल के बाद भुगतान) व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार अगस्त माह से सरकारी दफ्तरों में बिजली खपत की गणना के आधार पर पहले स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना होगा। तभी उनके दफ्तरों में बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। अब प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी किस विभाग का कितना बकाया ग्राम पंचायतें 54.145 करोड़ शिक्षा विभाग 12.163 करोड़, नगर निगम कोरबा 6.184 करोड़, नगर पालिका 6.180 करोड़, नगर पंचायतें 4.176 करोड़, महिला एवं बाल विकास विभाग 2.190 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 2.160 करोड़, तेजी से जारी है स्मार्ट मीटर लगाने का काम जिले में निजी ठेका कंपनी के माध्यम से पिछले 2 वर्षों से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। अब तक 65 प्रतिशत घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लग चुका है। विकासखंड स्तर पर चरणबद्ध तरीके से चल रहे इस अभियान के तहत अब धीरे-धीरे स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ग्राम पंचायतों में भी स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं। ताकि तकनीकी खामियों को दूर कर शत-प्रतिशत प्री-पेड व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

विद्युत विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कोरबा जिले में ही सरकारी विभागों सहित बड़े बकायादारों और आम उपभोक्ताओं की गणना करने पर कुल बकाया राशि अब 402 करोड़ 83 लाख रुपए तक पहुंच गई है।

ओडिशा से दो कार में भरकर ला रहे थे 62 लाख का सूखा नशा

सुकमा। सूखे नशे की अंतर्राज्यीय तस्करी के खिलाफ सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 60 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों कर्नाटक के बीदर के रहने वाले हैं। तस्करी के लिए दो स्वीफ्ट कार का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों के पास से फर्जी नंबर प्लेट, कैश और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एर्राबोर पुलिस को सूचना मिली कि मुखबिर से मिली कि ओडिशा से दो सफेद रंग की कारों में अवैध गांजा परिवहन किया जा रहा है। इसके बाद एर्राबोर बाजार के पास एनएच-30 पर घेराबंद कर दो वाहनों को रोका गया। तलाशी के दौरान कारों की तलाशी ली गई, साथ ही युवकों से पूछताछ करने पर उन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कुल 50 पैकेट अवैध गांजा बरामद किया, जिसका वजन 68 किलोग्राम पाया गया। बाजार में इसकी कीमत 62,63,100 रुपए आंकी गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना लेकर आई। गिरफ्तारी आरोपियों में कर्नाटक के बीदर जिला के सोहेल खान, अब्दुल अदील और आकाश गौड़ नाम शामिल है। इनके खिलाफ धारा 20(ड्ड)(द्वद्व)(ष्ट), 29 एनडीपीएस एक्ट और धारा 318(2), 340 बीएनएसएस दर्ज किया गया है। दो कारें, फर्जी नंबर प्लेट, मोबाइल और नगदी बरामद किया गया है।

धमतरी के चावल कारोबारी की हत्या का खुलासा

धमतरी। धमतरी जिले के बहुचर्चित नारी महानदी पुल हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। करीब 10 दिनों तक चली गहन जांच, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की पड़ताल और वैज्ञानिक तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह चावल कारोबार में प्रतिस्पर्धा और उससे उपजी रंजिश थी। मामले में 21 वर्षीय बिरेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार 22 जुलाई को कुरूद थाना क्षेत्र स्थित नारी महानदी पुल पर कुंडेल निवासी 27 वर्षीय नीरज साहू का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। उसके गले और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जबकि उसकी पिकअप वाहन भी घटनास्थल पर खड़ी मिली थी। घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की।

एसपी भावना पांडेय के निर्देशन में कुरूद थाना, मगरलोड थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाई गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े संभावित मार्गों के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों का गहन विश्लेषण किया। कई संदिग्धों से पूछताछ और लगातार साक्ष्यों के मिलान के बाद पुलिस मगरलोड के सांकरा के रहने वाले आरोपी बिरेंद्र कुमार साहू तक पहुंचने में सफल रही। एसपी भावना पांडेय के मुताबिक आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए बताया कि वह और मृतक दोनों चावल का कारोबार करते थे। नीरज का कारोबार लगातार बढ़ रहा था और उसकी आमदनी भी अधिक थी। इसी बात को लेकर वह अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या और रंजिश रखने लगा था। मौका मिलने पर उसने नारी महानदी पुल के सुनसान हिस्से में नीरज को रोककर कैंची और पाना से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी।

एसपी भावना पांडेय ने बताया कि यह मामला पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि शुरुआत में घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और सुराग भी बेहद सीमित थे। इसके बावजूद पुलिस टीम ने हार नहीं मानी। घटनास्थल से लेकर संभावित भागने के रास्तों तक लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की बारीकी से जांच की गई।

वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों को एक-एक कर जोड़ा गया और हर छोटी जानकारी का विश्लेषण किया गया। इसी लगातार प्रयास का परिणाम रहा कि आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली। आधुनिक तकनीक, साइबर जांच और टीमवर्क की बदौलत इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा संभव हो पाया। जिले में गंभीर अपराध करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी- भावना पाण्डेय,एसपी

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कैंची और पाना भी बरामद कर लिया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

वैज्ञानिक खेती अपनाकर, करेला उत्पादन में किसान बजरंग बने प्रेरणा स्रोत

जीपीएम। गौरेला विकासखंड के ग्राम कोटरियाडांड के प्रगतिशील किसान बजरंग ने उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में एक एकड़ क्षेत्र में करेला की वैज्ञानिक खेती कर बेहतर उत्पादन एवं आय अर्जित करते हुए क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पूर्व में श्री बजरंग परंपरागत खेती करते थे, जिससे उत्पादन और आय अपेक्षाकृत कम थी।

उद्यानिकी विभाग द्वारा उन्हंश सब्जी फसलों की वैज्ञानिक खेती, उन्नत उत्पादन तकनीकों तथा फसल प्रबंधन का प्रशिक्षण एवं नियमित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके बाद उन्होंने मल्चिंग, ट्रेलिस प्रणाली, संतुलित पोषण प्रबंधन, समय पर सिंचाई तथा समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया। इन तकनीकों के उपयोग से करेला की फसल का विकास बेहतर हुआ, गुणवत्तायुक्त उत्पादन प्राप्त हुआ तथा बाजार में फसल का उचित मूल्य मिलने से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्तमान में करेला की खेती उनके लिए लाभकारी व्यवसाय का रूप ले चुकी है। श्री बजरंग की सफलता से ग्राम कोटरियाडांड सहित आसपास के क्षेत्रों के किसान भी उद्यानिकी विभाग की योजनाओं एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि विभागीय मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीकों और किसानों की मेहनत के समन्वय से सीमित भूमि पर भी अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

घर में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों पर जानलेवा हमला, फिर खुद मिला मृत

धमतरी। वनांचल क्षेत्र नगरी के बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के कर्राघाटी गांव में शुक्रवार देर रात एक तेंदुआ अचानक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। तेंदुए ने एक घर के भीतर घुसकर दो ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हैरत की बात यह भी है कि तेंदुआ भी घर के अंदर मृत अवस्था में पड़ा मिला। बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के कर्राघाटी गांव में देर रात एक तेंदुआ जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया। इसके बाद वह एक घर में घुस गया। उस समय धरम नेताम (40 वर्ष) और गांधी नेताम (करीब 50 वर्ष) घर पर मौजूद थे। तेंदुए के अचानक हमला करने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और घायलों को तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया गया। परिजन और ग्रामीणों ने तत्काल दोनों घायलों को नगरी सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।रात में तेंदुआ आया। तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया, जिससे घायल हो गया।

गेंदा फूल की खेती से किसान हेमचंद साहू की बदली तस्वीर

गरियाबंद। पारंपरिक धान की खेती से सीमित आय अर्जित करने वाले छुरा विकासखण्ड के ग्राम कसेकेरा के किसान हेमचंद साहू ने आधुनिक बागवानी तकनीकों को अपनाकर सफलता की नई मिसाल कायम की है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के सहयोग से उन्होंने 0.48 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई एवं मल्चिंग तकनीक के साथ गेंदा फूल की खेती शुरू की, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता से श्री साहू ने वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना सीखा। आधुनिक तकनीक अपनाने से उनका उत्पादन बढ़ा, लागत नियंत्रित रही और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। उनके द्वारा गेंदा फूल की बिक्री स्थानीय बाजार के साथ-साथ रायपुर में भी की गई, जिससे उन्हें लगभग दो लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। साहू बताते हैं कि पहले धान की खेती से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन था, लेकिन अब फूलों की खेती ने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है।

चिट्टा सिंडिकेट पर प्रहार, छह आरोपी माल समेत गिरफ्तार

दुर्ग। पुलिस ने नशे के खिलाफ एक और बड़ा प्रहार करते हुए भिलाई-दुर्ग क्षेत्र में पैर पसार रहे संगठित हेरोइन गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है. सुपेला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि खबर मिली थी कि गिरोह का मास्टरमाइंड, गुरमीत सिंह रंधावा पंजाब से सस्ते दाम पर चिट्टा मंगाकर दुर्ग जिले में खपाता है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जुनवानी स्थित शंकराचार्य अस्पताल के पीछे घेराबंदी की।मौके से 6 आरोपियों को धर दबोचा गया, जिनके पास से 18 ग्राम शुद्ध हेरोइन, 6 स्मार्टफोन्स और नशा सेवन की सामग्री जब्त की गई। जब्त माल की कीमत करीब 3.50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी गुरमीत सिंह रंधावा,गगनदीप सिंह,शुभम कुमार बैस, ?जी। विनित,उत्तम सिंह और अब्दुल कादिर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ख), 27 और 29 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस आरोपियों के मोबाइल डेटा, बैंक खातों और पूरे सप्लाई नेटवर्क को खंगाल रही है।

बन्दर ने 5 माह के मासूम को पानी से भरे ड्रम में डाला

सरगुजा। जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरी कला में जंगली बंदरों ने जमकर आतंक मचाया। बस्ती में घुसे बंदर ने उत्पात मचाते हुए पालने में सो रहे 5 माह के मासूम बच्चे को उठाकर पानी से भरे ड्रम में डाल दिया। गंभीर हालत में बच्चे को पहले लखनपुर अस्पताल लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार, जंगली बंदर अचानक बस्ती में घुस आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बंदर के डर से लोग अपने-अपने घरों में छिप गए। इसी दौरान बंदर एक घर में घुस गया और पालने में सो रहे 5 माह के मासूम को उठाकर ले जाने लगा। कुछ ही दूरी पर उसने बच्चे को पानी से भरे नीले ड्रम में डाल दिया। परिजनों ने तत्काल बच्चे को ड्रम से बाहर निकाला और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली बंदर को पकड़ने में लगी है।

सरकारी चावल और चना की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी

बस्तर। आदिवासी बाहुल्य बस्तर में सरकारी राशन सामग्रियों की कालाबाजारी का मामला लगातार सामने आ रहा है। खाद्य विभाग ने 3 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने 378 बोरी चावल, 6 बोरी चना सहित ट्रक को जब्त किया है। जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर ने बताया कि खाद्य विभाग को सूत्रों से जानकारी मिली थी, जिसके बाद जगदलपुर के अनुपमा चौक स्थित भवानी चाट भंडार के पीछे बाड़ा में स्थित गोदाम की जांच की गई। जांच के दौरान दुकान और गोदाम में सरकारी चावल और चना का भंडारण मिला। दुकान के सामने ट्रक खड़ी थी,जिसमें चावल लोड किया जा रहा था। खाद्य अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान दुकान और ट्रक में 378 बोरा चावल मिला। वहीं 6 बोरा चना भी मिला, जिसका वजन 3 क्विंटल है। 100 बोरा राशन बारदाना मिला। इन सभी सामग्रियों को जब्त कर जवाहर वार्ड स्थित राशन दुकान को सुपुर्दगी में दिया गया है। लोड हो रहे ट्रक को भी जब्त कर सिटी कोतवाली को सुरक्षा के लिए सौंप दिया गया है।

महिला आयोग अध्यक्ष ने लिया अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा

अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डॉ. ममता साहू धमतरी पहुंचीं.

धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार डॉ। ममता साहू धमतरी पहुंचीं। जिले में महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और पीड़ित महिलाओं के लिए संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जिला अस्पताल के साथ-साथ सखी सेंटर का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। डॉक्टरों और मरीजों से भी सीधे संवाद किया। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डॉ।

ममता साहू ने विशेष रूप से प्रसूति गृह, नवजात शिशु वार्ड और प्री-मैच्योर बच्चों के लिए तैयार किए गए विशेष वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में इस समय 24 प्री-मैच्योर बच्चों का उपचार चल रहा है। इन बच्चों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, डॉक्टरों की उपलब्धता, उपकरणों, एंबुलेंस व्यवस्था और संपूर्ण उपचार प्रणाली को जाना। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कुछ कमियां जरूर सामने आई हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दिन अस्पताल में पांच प्रसव हुए थे। उन्होंने स्वयं प्रसूति कक्ष का निरीक्षण किया, जहां साफ-सफाई और व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं। डॉ। ममता साहू ने मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की। मरीजों ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनसे किसी प्रकार के पैसे की मांग नहीं की गई है। इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मरीजों का विश्वास बना रहना सबसे महत्वपूर्ण है। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी सामने आया। इस पर डॉ। ममता साहू ने कहा कि धमतरी जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस संबंध में राज्य शासन को पत्र लिखकर रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की जाएगी ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

विचाराधीन बंदी की मौत मामले में हत्या का केस दर्ज

बिलासपुर। केंद्रीय जेल बिलासपुर में बंद विचाराधीन बंदी श्रवण सूर्यवंशी उर्फ श्रवण ताम्रे की मौत के मामले में पुलिस ने दो साल बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने न्यायिक जांच रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पुलिस के अनुसार ग्राम मोहरा, थाना सीपत निवासी 34 साल का श्रवण सूर्यवंशी आबकारी अधिनियम के एक केस में विचाराधीन बंदी के रूप में केंद्रीय जेल बिलासपुर में था। 21 जनवरी 2024 को तबीयत बिगड़ने पर जेल मेडिकल ऑफिसर की सलाह पर उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 जनवरी 2024 की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उस समय मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की गई थी। मामले की न्यायिक जांच मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निकसन डेविड लकड़ा ने की। जांच के दौरान शव परीक्षण, एफएसएल, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, वीडियोग्राफी, पंचनामा और गवाहों के बयान सहित सभी साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सिर में आई गंभीर चोट और उससे हुई कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि चोट किसी कठोर वस्तु से लगना संभव है, जबकि रासायनिक परीक्षण में किसी प्रकार का जहर नहीं पाया गया। मृतक की पत्नी, पिता और अन्य परिजनों ने जांच के दौरान बताया कि श्रवण को आबकारी केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में जेल भेजा गया। परिवार को उसकी तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की सूचना बाद में मिली। हालांकि किसी ने भी किसी व्यक्ति पर सीधे संदेह नहीं जताया। न्यायिक जांच प्रतिवेदन 22 जुलाई 2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपा गया था। सिविल लाइन थाना प्रभारी किशोर केंवट ने बताया कि इसके बाद केंद्रीय जेल प्रशासन और पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर के निर्देश पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 30 जुलाई 2026 को हत्या का अपराध दर्ज करने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

आदिवासी सम्मान कांग्रेस को क्यों चुभ रहा है : केदार कश्यप

बस्तर पंडुम और राष्ट्रपति भवन में आदिवासी प्रतिनिधियों की भेंट पर कांग्रेस की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण

रायपुर। वनमंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बस्तर पंडुम और राष्ट्रपति भवन में बस्तर के आदिवासी प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से हुई भेंट को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक हताशा नहीं, बल्कि बस्तर के जनजातीय समाज, उसकी संस्कृति, परंपराओं और अस्मिता का खुला अपमान है। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बस्तर की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और आदिवासी गौरव का महापर्व है। जिस आयोजन ने बस्तर के लोक कलाकारों, मांझी-चालकी व्यवस्था और जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाया, उसी पर सवाल उठाना बताता है कि कांग्रेस आदिवासी समाज के सम्मान को भी राजनीतिक चश्मे से देख रही है।

कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन में बस्तर के आदिवासी प्रतिनिधियों की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से हुई ऐतिहासिक भेंट का भी उपहास उड़ाने का प्रयास किया है। आज़ादी के दशकों बाद पहली बार बस्तर के पारंपरिक वेशभूषा में सजे जनजातीय प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया, उनसे आत्मीय संवाद हुआ और उनकी संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान मिली। यह हर बस्तरवासी और पूरे जनजातीय समाज के लिए गर्व का विषय है। ऐसे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण का मज़ाक उड़ाना केवल राजनीतिक अपरिपक्वता नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि जिस आदिवासी समाज को

कांग्रेस ने दशकों तक केवल वोट बैंक समझकर देखा, आज जब उसी समाज को सम्मान, पहचान और राष्ट्रीय मंच मिल रहा है तो कांग्रेस को आखिर इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? देशभर में बस्तर की संस्कृति की चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस इस गौरवपूर्ण अवसर में भी राजनीति खोज रही है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस को पहले यह बताना चाहिए कि अपने लंबे शासनकाल में उसने बस्तर की संस्कृति, लोक कलाकारों और पारंपरिक व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कौन-सा ऐतिहासिक कार्य किया था। कांग्रेस के शासन में बस्तर की पहचान विकास और संस्कृति से नहीं, बल्कि नक्सली हिंसा, भय और पिछड़ेपन से जुड़ गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर शांति, विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक गौरव की नई पहचान बना रहा है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर पंडुम पर सवाल उठाकर और राष्ट्रपति भवन में आदिवासी प्रतिनिधियों के सम्मान का उपहास कर कांग्रेस ने केवल सरकार का नहीं, बल्कि उन हजारों आदिवासी कलाकारों, मांझी-चालकी व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों और पूरे बस्तर के स्वाभिमान का अपमान किया है, जिन्होंने इस गौरवपूर्ण अवसर को संभव बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बस्तर की सकारात्मक तस्वीर से परेशानी हो रही है क्योंकि उसकी राजनीति हमेशा भय, भ्रम और पिछड़ेपन पर टिकी रही है। लेकिन अब बस्तर बदल चुका है। आज का बस्तर अपनी संस्कृति पर गर्व करता है, विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और पूरे देश में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। इस परिवर्तन को कांग्रेस चाहे जितना नकारने या उसका उपहास करने का प्रयास करे, बस्तर की जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी।

डबल इंजन सरकार किसानों और युवाओं के हित में निरंतर ले रही ऐतिहासिक फैसले : चौधरी

■ **पीएम-किसान योजना को 2030-31 तक विस्तार, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और नई खेलो इंडिया योजना को मिली मंजूरी**

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि डबल इंजन सरकार अन्नदाताओं, युवाओं और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर संकल्पबद्ध होकर ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले देश के किसानों, खिलाड़ियों और ऊर्जा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

श्री चौधरी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (च्ड-ज्ञ्-छ) योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रूपये के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय करोड़ों किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा तथा कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाएगा। उन्होंने इस किसान हितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,070 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (च्ड-ै-ल) को भी स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जलाशयों का बेहतर उपयोग होगा तथा देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी।

श्री चौधरी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 36,441 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ नई खेलो इंडिया योजना को स्वीकृति देना देश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इस योजना के माध्यम से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, उच्चस्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान, आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण शिविर तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की समृद्धि, हरित ऊर्जा के विस्तार और युवाओं की खेल प्रतिभा को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन निर्णयों से विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिलेगी।

नोटिस और पोस्टर-वार के खेल से बेनकाब हुआ कांग्रेस का तथाकथित अनुशासन : भाजपा

■ **प्रदेश प्रवक्ता ठोकने ने कहा : कांग्रेस में छिड़ा बैज बनाम पटेल का घमासान, पद लोलुपता और अंतर्कलह से सड़कों पर आई पार्टी की गुटबाजी**

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर मचे राजनीतिक घमासान, बढ़ती पद लोलुपता और अंतर्कलह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने तीखा तंज कसा है। बैज बनाम पटेल की जंग पर हमला बोलते हुए ठोकने ने कहा कि सत्ता जाते ही कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है और अब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के भीतर खुलकर पोस्टर वार और सिर-फुटौव्वल शुरू हो चुकी है।

ठोकने ने कहा कि पूर्व मंत्री उमेश पटेल को पीसीसी चीफ बनाने की मांग उठने के बाद जिस तरह से पूर्व जिलाध्यक्ष अरुण मालाकार को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में सच बोलने वालों का दमन किया जा रहा है। खाबो लाठी, जाबो जेल, हमर नेता उमेश पटेल जैसे नारों के साथ सोशल मीडिया पर जारी यह जंग सिर्फ कुछ समर्थकों की नारेबाजी नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और उमेश

पटेल के खेमों के बीच छिड़ी खुली राजनीतिक लड़ाई है। ठोकने ने कहा कि रायगढ़, बस्तर, रायपुर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह लामबंदी दर्शाती है कि कांग्रेस के भीतर डेढ़ दशक बाद कुर्सी के लिए ऐसा घमासान मचा है, जो अब छिपाए नहीं छिप रहा। एक तरफ बैज अपनी कुर्सी बचाने के लिए नोटिस की लाठी चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल समर्थक नेता इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।

ठोकने ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ ही न बची हो, वह जनता के मुद्दों पर क्या बात करेगी? कांग्रेस नेता आज न तो विपक्ष की भूमिका निभाने के योग्य बचे हैं और न ही अपना संगठन संभालने के। अपनी-अपनी निष्ठाएँ चमकाने और पद पाने की लोलुपता में कांग्रेस अब नोटिस और पोस्टर की पार्टी बनकर रह गई है। जनता सब देख रही है कि किस तरह अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग अलापने वाले ये नेता केवल पद के लिए एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं!

सीएम साय की बड़ी घोषणा, आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को 20-20 लाख देगी सरकार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुलगाम (जम्मू-कश्मीर) आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने घटना की निंदा करते हुए मृतात्माओं की शांति की प्रार्थना की।

दिल्ली के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बस्तर पंडुम के विजेताओं का राष्ट्रपति ने सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नक्सल मुक्त बस्तर में जो गतिविधि चल रही है उसकी जानकारी दी, वहां विद्युतीकरण की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूर करने का आयोजन किया, आयुर्वेद का एम्स खोलने की भी मांग प्रधानमंत्री से की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि विकास के काम तेजी से होंगे। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लखपति दीदी को लेकर सम्मेलन होगा।

वहीं महानदी जल विवाद को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री के साथ हुई बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों प्रदेश के हित को देखते हुए निर्णय होगा, आने वाले तीन महीने में जल बंटवारे का निर्णय हो जाने की उम्मीद है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन मिलने वाला है। रेल मंत्री से मुलाकात में इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुछ और रेल लाइन की स्वीकृति को लेकर भी बातचीत हुई है। बस्तर में भी किरंदुल से बीजापुर जैसी जगहों के लिए रेल लाइन पर चर्चा हुई है।

सीएम साय ने बताया कि नये मोबाइल टावर के लिए भी केंद्रीय मंत्री से बात हुई है, नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में पहले जो 500 से ज्यादा मोबाइल टावर मिले उसके लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा बस्तर के 400 से ज्यादा गांवों में बिजली के लिए विभागीय केंद्रीय मंत्री से बात की है। बस्तर में कुछ क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आतंकी हमले को लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पलायन वाले बयानों पर कहा कि ऐसी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में काम की कोई कमी नहीं है, विकसित भारत जी राम जी के जरिए भी रोजगार मिल रहा है। नई औद्योगिक नीति आने के बाद भी काम मिल रहा है। वहीं आतंकी हमले पर कांग्रेस के बयान पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी और आरएसएस के हर चीज में साजिश नजर आती है, उन्हें अपना चश्मा बदलने की जरूरत है।

उमर सरकार मृतक मजदूरों के परिवारों को देगी 10 लाख

श्रीनगर-रायपुर। कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों के परिवारों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 10-10 लाख की अनुग्रह राशि देने का एलान किया है। जिला प्रशासन की ओर से पहले ही 6-6 लाख की तत्काल सहायता घोषित की गई थी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में मजदूरों की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की है और निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएमओ के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाने वाली यह 10 लाख रुपये की सहायता राशि जिला प्रशासन की ओर से घोषित 6 लाख रुपये की तत्काल राहत राशि के अतिरिक्त होगी।

कुलगाम आतंकी हमले की वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की कड़ी निंदा

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में छत्तीसगढ़ के श्रमिकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यंत दु:खद एवं निंदनीय बताया है। मंत्री श्री चौधरी ने हमले में दिवंगत श्रमिक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायल श्रमिक के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि इस दु:खद घटना से पूरा छत्तीसगढ़ मर्माहत है और उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय सुरक्षा बल इस कायराना हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे और आतंकियों को उनके कृत्य की कठोर सजा मिलेगी।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग
छुईखदान जिला-खैरागढ़-छुईखदान - गण्डई (छ.ग.)
Office Email ID, eewrckn@cgwrd.in / Fax & Ph.No. 07743-263628

क्रमांक 3095/व.ले.लि. छुईखदान, दिनांक 30/07/2026

निविदा निरस्तीकरण आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक 15/व.ले.लि./2025-26, दिनांक 02.02.2026, सिस्टम टेंडर नंबर 184680 प्रथम आमंत्रण खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखंड छुईखदान अंतर्गत् कांशीनाला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर आर.डी. 0 मी. से आर.डी. 2845 मी. तक जीर्णोद्धार एवं सीमेंट कांकीट लाईनिंग का कार्य साथ ही 10 नग इनलेट, 01 नग इस्केप, 05 नग व्ही.आर. बी., 02 नग फाल का निर्माण कार्य एवं कुलाबा पाईप फिक्सिंग कार्य का न्यूनतम निविदा दर स्वीकृति एवं इस कार्यालय द्वारा अनुबंध हेतु आमंत्रण पत्र जारी करने के पश्चात् निविदाकार अनुबंध हेतु अक्षम रहे, इस कारण उक्त निविदा, निविदा प्रपत्र की कंडिका 3.26 अंतर्गत निरस्त किया जाता है।

जी-252606421

कार्यपालन अभियंता,
जल संसाधन संभाग, छुईखदान
जी-262702497/6 **जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)**

कुलगाम में दो मजदूरों की हत्या, दीपक बैज ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना

■ **कहा- धर्म पूछकर गोली मारना षडयंत्र तो नहीं?**

रायपुर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को छत्तीसगढ़ के मजदूरों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है।

दीपक बैज ने कहा कि दो मजदूरों को धर्म पूछकर गोली मारी गई। जब-जब केंद्र सरकार कमजोर दिखाई देती है या आंतरिक रूप से घिर जाती है, तो इस तरह की घटना घटती है। कहीं ये षडयंत्र तो नहीं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। क्या केंद्र के खिलाफ बने माहौल को डायवर्ट करने के लिए यह हादसा कराया गया है?

वहीं उन्होंने आगे कहा कि आतंकवादी इतने सुरक्षाबलों के बीच कैसे घुसकर गोली मार रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है, षड्यंत्र हैं। इसकी जांच होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ के मजदूर को गोली मारा जाना ये केंद्र और राज्य सरकार के लिए सवाल खड़े करता है। पुरानी मनरेगा योजना बंद करने के बाद सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है, जिससे आम ग्रामीणों को लाभ मिल सके। पलायन कर मजदूरी करने वालों को मारा गया। इतिहास

इसी के साथ ही दीपक बैज ने भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले हमले में जो कार्रवाई हुई उसी तरह दूसरी बार के अटैक के बाद भी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ट्रेड डील की वजह से ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ही रोक दिया। मोदी सरकार पूरी तरह बेबस और फेल हो चुकी है। जेन जी के विरोध के बाद सरकार की स्थिति ठीक नहीं है।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, कार्यालय मुख्य अभियंता
गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, जगदलपुर (छ.ग.)

ई. प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in
(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 196308/निविदा सूचना क्र. 11/ व.ले.लि. / 2026-27 दि. 30.07.2026

निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 20.08.2026 17.30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है-
कार्य का नाम- कांकेर जिले के विकासखंड दुर्गकोंदल के दियागांव जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य ।
अनुमानित लागत- रु. 409.10 लाख (जी.एस.टी. छोड़कर)
(एस.ओ.आर. दिनांक 01.05.2025 से प्रचलित (यथा संशोधित दिनांक 08.08.2025)
अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 06.08.2026 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते है।

नोट :- निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है। इस निविदा में जल संसाधन विभाग द्वारा जारी निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण पत्र जिसकी वैधता दिनांक 30.09.2026 तक है, वह लागू होगी।

कार्यपालन अभियंता,
जल संसाधन संभाग, कांकेर
कृते- मुख्य अभियंता गोदावरी कछार
जी-262702484/10 **जल संसाधन विभाग, जगदलपुर छ.ग.**

संक्षिप्त समाचार

वित्तमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल में पदक विजेता नीरज चोपड़ा एवं यशवीर को दी बधाई

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा तथा कांस्य पदक जीतने वाले यशवीर सिंह को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन, कठिन परिश्रम और अटूट समर्पण के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। उनकी उपलब्धि प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह का उत्कृष्ट प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स की बढ़ती शक्ति और देश के खिलाड़ियों की विश्वस्तरीय क्षमता का प्रमाण है। उनका संघर्ष, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण देश के युवाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि समस्त देशवासियों को दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने नीरज चोपड़ा एवं यशवीर सिंह को पुन: हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य तथा आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करने की शुभकामनाएं दीं।

सुरक्षा के दृष्टि से केन्द्रीय जेल रायपुर में मुलाकात व्यवस्था में अस्थाई परिवर्तन

रायपुर। केन्द्रीय जेल रायपुर में विगत माह बंदियों से मुलाकात के दौरान कुछ परिजनों द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्रियों में प्रतिबंधित वस्तुएँ छिपाकर जेल परिसर के भीतर पहुँचाने का प्रयास किया गया था। जेल शासन के सघन तलाशी एवं सतर्क सुरक्षा व्यवस्था के कारण ऐसे सभी प्रयास विफल कर दिए गए तथा संबंधित प्रतिबंधित सामग्री जप्त कर आवश्यक कार्यवाही की गई। अधीक्षक केन्द्रीय जेल रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जेल की सुरक्षा एवं अनुशासन को दृष्टिगत रखते हुए और सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जेल प्रशासन द्वारा एहतियातन बंदियों के दैनिक उपयोग की कुछ चयनित सामग्रियों को जेल केन्टीन से क्रय कर बंदियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अन्य सभी स्वीकृत सामग्री पूर्ववत् नियमानुसार बंदियों के परिजन स्वयं उपलब्ध करा सकते हैं।

कुलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों से विजय शर्मा ने की बात

रायपुर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दीपक रात्रे एवं भूपेन्द्र की निर्मम हत्या की सूचना मिलते ही उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान तत्काल दोनों दिवंगतों के परिजनों से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने शोकाकुल परिवारों को ढांढस बंधाते हुए इस कठिन समय में राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री शर्मा ने अधिकारियों को भी आवश्यक समन्वय एवं हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घटना ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक में डाल दिया है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध है। आतंकवाद के ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और इस नृशंस हमले में शामिल आतंकियों को उनके अपराध की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि आतंकियों को उनके कृत्य का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और इस हमले का बदला अवश्य लिया जाएगा। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा दोनों पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह संवेदनशील निर्णय शोक संतप्त परिवारों को कठिन समय में संबल प्रदान करेगा तथा राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

राज्य में मानसून मेहरबान : अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून का रुख लगातार अनुकूल बना हुआ है। एक जून से 01 अगस्त 2026 तक प्रदेश में औसतन 557.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले दस वर्षों की इसी अवधि की औसत 541.2 मिमी वर्षा का 103 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि इस वर्ष प्रदेश में अब तक सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। प्रदेश के कई जिलों में वर्षा ने सामान्य स्तर को उल्लेखनीय रूप से पीछे छोड़ दिया है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ 193.2 प्रतिशत वर्षा के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है। इसके बाद नारायणपुर (153 प्रतिशत), महासमुंद (146.7 प्रतिशत), रायपुर (135 प्रतिशत), गरियाबंद (134.3 प्रतिशत), जांजगीर-चांपा (130.7 प्रतिशत), बलौदाबाजार (124.1 प्रतिशत), बालोद (123 प्रतिशत), धमतरी (118.6 प्रतिशत), दुर्ग (117 प्रतिशत), सक्ती (115.7 प्रतिशत), बलरामपुर (111.3 प्रतिशत), बिलासपुर (111 प्रतिशत), मुंगेली (106.5 प्रतिशत), राजनांदगांव (106.1 प्रतिशत) तथा दंतेवाड़ा (106 प्रतिशत) में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। वहीं सामान्य वर्षा के करीब रहने वाले जिलों में कोरिया (99.7 प्रतिशत), कोरबा (97.8 प्रतिशत), रायगढ़ (97.1 प्रतिशत), मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (96.6 प्रतिशत), गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (95.8 प्रतिशत) और सूरजपुर (95.7 प्रतिशत) शामिल हैं।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आर पार की लड़ाई

सनत जैन

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह की रास्सा-कस्सी देखने को मिल रही है, उससे स्पष्ट है, विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक तेवर में है। जंतर मंतर में हुए कॉकरोच आंदोलन के बाद देश भर के युवाओं में जो गुस्सा देखा गया, देश में सेकड़ों स्थान पर प्रदर्शन हुए। उसने विपक्ष को एक नई ताकत दे दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मौके को आपदा में अवसर के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से सरकार के खिलाफ जेन-जी और जेन-अल्फा अपने परिवार से विद्रोह करके सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतरा, तरह-तरह से बिना डरे हुए उसने मुखरता के साथ अपनी बात कही। युवाओं के इस आंदोलन को देखकर देश में जो डर और भय का माहौल बना था, ऐसा लगता है कि वह डर और भय खत्म हो गया है। छात्रों के साथ-साथ अब अन्य संगठन भी अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। उनके भी वैसे ही आक्रामक तेवर हैं, जैसे जंतर मंतर में या छात्र आंदोलन के दौरान देखने को मिले थे। इसने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किसान संगठनों ने भोपाल तक मूंग खरीदी को लेकर कूच किया। उन्होंने पुलिस के सारे बैरियर पार करते हुए मुख्यमंत्री निवास के करीब 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। जबकि सरकार ने कई किलोमीटर पहले से ही बेरीकैट लगाकर किसानों को रोकने का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया था। किसानों ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। मध्य प्रदेश सरकार ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। पुलिस अधिकारियों ने भी किसानों को रोकने के लिए जिस तरह से मुंबई की एक जेन-जी लड़की पुलिस वाहन के सामने आकर खड़ी हो गई थी ठीक वैसे ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किसानो की बस के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण किसानों को रुकना पड़ा। संसद के मानसून सत्र का दूसरा साप्ताह खत्म हो गया है। सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए संसद में जो बिल पेश किया था, वह पास हो गया है। इस बीच संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी और विपक्ष ने अब अपना निशाना गृहमंत्री की ओर कर लिया है। अब इस्तीफा और माफी को लेकर विपक्ष अड़ गया है, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री संसद की कार्रवाई में नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर विपक्ष और आक्रामक हो गया है। संसद परिसर में जिस तरह विपक्षी दल एकत्रित होकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पेलेट गन और एक-47 का मुद्दा दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण विपक्ष ने बुरी तरह से सरकार को घेर लिया है। जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हो रहा था, इसका लाइव प्रसारण होने से पुलिस और सरकार की परेशानी बढ़ रही है। सरकार को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो बिसात विपक्ष बिछा रहा है उसी पर सफाई देने के लिए सरकार को आगे आना पड़ रहा है। पुलिस के परिवारजनों को मीडिया के सामने उतारा गया है। शुक्रवार को आसंदी से सांसदों को चेतावनी दी जा चुकी है कि वह संसद परिसर में कोई ऐसा प्रदर्शन ना करें जिसके कारण उन पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन यह सारे प्रयास कहीं पर भी कारगर होते हुए दिख नहीं रहे हैं। विपक्ष इस बार आर-पार की लड़ाई लड़ने की मुद्रा में है। उसका एकमात्र लक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा है। विपक्ष का मानना है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक प्रतीक था। गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा पूरी सरकार को हिलाकर रख देगा। विपक्ष सरकार की आपदा में अपने लिए सबसे बड़ा अवसर देख रहा है।

प्रधान के इस्तीफे के बाद कई राज्यों में बढ़ा सियासी पारा

अजय बोकिल

दिल्ली में पेपरलीक के खिलाफ जेन जी के आंदोलन की समाप्ति और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के आफ्टर इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। आंदोलन का राजनीतिक फोकस अब राज्यों की तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां दस राज्यों में पेपर लीक और परीक्षा भ्रष्टाचार के मामलों में सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों के इस्तीफों की मांग की जा रही है और कोई राज्य सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। उधर जेन ज़ी आंदोलन के प्रणेता अभिजीत दिपके ने चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार अपने वचनों से फिरी तो फिर से आंदोलन होगा।

इधर राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन से हमले का आदेश किसने दिया और उनके साथ मारपीट करने का मुद्दा उठाते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अपनी राजनीतिक पैलेट गन तानते हुए इस्तीफे की मांग कर दी है तो दूसरी तरफ सरकार और सत्तासीन भाजपा ने आंदोलन के दौरान किसी भी तरह से गोली चलने से इंकार करते हुए आरोप लगाया है कि जेन ज़ी आंदोलन की कामयाबी की क्रेडिट अपने खाते में लिखवाने में नाकाम रहे राहुल गांधी अब 'क्रेडिट चोरी' पर उतर आए हैं। हालांकि राहुल गांधी के इस राजनीतिक पैलेट गन का गृह मंत्री और मोदी सरकार पर खास असर होगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन राहुल की यह मांग जरूर जायज है कि सरकार यह तो बताए कि पैलेट गन चली किसके आदेश से और जिन्हें इसकी गोलियां लगीं वो कौन हैं, हैं भी या नहीं और हैं तो उनकी क्या हालत है। क्योंकि देश में पैलेट गन अमूमन केन्द्रीय सुरक्षा बलों या उन राज्यों की पुलिस के पास ही है, जो आतंकवाद और अलगाववाद से प्रभावित हैं। दिल्ली में इसका प्रयोग जरूर सवाल खड़े करता है।

बीते कुछ वर्षों में देश में 'जेहाद' और 'चोरी' प्रत्यय से बनने वाले नए-नए शब्दों की बाढ़- सी आ गई है। मामला 'लव जेहाद' से शुरू हुआ था और अब 'कारपोरेट जेहाद' तक के आन पहुंचा है। इसी तरह देश में चुनाव आयोग के मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान ने भी हिंदी शब्दकोश को समृद्ध करने का काम अलग तरीके से किया हैं, जिसकी वजह से वोट काटे जाने को 'वोट चोरी', सीट हारने को 'सीट चोरी' या फिर चढ़ावे में हाथ मारने के लिए

'चढ़ावा चोरी' आदि शब्द रूढ़ हुए। परस्पर राजनीतिक हमले के अब ये नए सामाजिक जुमले हैं। मीडिया ने इन्हें और लोकप्रिय बनाया।

इन सबके पीछे निशाना मुख्य रूप से मोदी सरकार ही रही है, लेकिन अब इसी ट्रेंड के पलटवार के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि जेन जी आंदोलन के मामले में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रवैया भी बिना कुछ खास किए, जेन ज़ी आंदोलन की क्रेडिट को चुराकर अपने खाते में जमा करने का है। क्योंकि कांग्रेस इस आंदोलन से शुरू में यह मानकर दूर ही रही थी कि यह उस आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित है, जो पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक दुश्मन नंबर वन है। हालांकि नीट पेपर लीक का मुद्दा वो अपने ढंग से अलग मंचों पर उठा रहे थे।

आंदोलन पकने पर जरूर राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों के दमन के विरोध और केन्द्रीय मंत्री प्रधान के इस्तीफे के समर्थन में पीएम आवास पर धरना देकर उसे नई धार देने की कोशिश तो की। लेकिन उधर सरकार ने पहले ही आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से समझौता कर उन्हें आंदोलन से अलग किया और बाद में आंदोलन की जनक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से सीधा समझौता कर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को हाशिए पर डाल दिया। आंदोलन के समर्थकों ने इसे मोदी सरकार की पहली करारी राजनीतिक हार माना तो मोदी समर्थकों की निगाह में यह 'दो कदम आगे बढ़ने के लिए यह एक कदम पीछे खींचने' की रणनीति का हिस्सा है, जिसके नतीजे आगामी चुनावों में दिखाई देंगे। (वैसे इसकी पहली परीक्षा दतिया सहित तीन विस उपचुनावों में ही हो जाएगी)।

यह भी सही है कि शुरू में सरकार ने इस आंदोलन को बढ़ने दिया। बाद में तमाम युवा सड़कों पर उतर आए तो आंदोलन बेकाबू और हिंसक होने के डर से सरकार ने प्रधान का इस्तीफा करवा कर उस पर पानी डाल दिया। बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी का अमित शाह पर हमला, संसद में नहीं बोलने देने तथा आंदोलनकारी छात्रों का बर्बर दमन जैसे आरोप सप्रेटा दूध से मलाई निकालने की कोशिश ज्यादा है, क्योंकि आंदोलन की मुख्य घटक सीजेपी भी उनके साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में कांग्रेस इस आंदोलन का कितना राजनीतिक लाभ उठा पाएगी और मोदी विरोधी माहौल कितना पक पाएगा, यह बड़ा सवाल है।

सवाल यह भी है कि अगर सरकार ने सीजेपी को दिए सभी वादों को पूरी तरह नहीं निभाया तो क्या जेन ज़ी फिर से इकट्ठे होकर सड़कों पर उतरेंगे, क्या यह फिर से संभव है, इन सवालो का जवाब अभी देना मुश्किल है। सीजेपी आगे क्या करेगी, कैसे करेगी, यह सवाल भी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी को अपने पाले में खींचने की राजनीतिक कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। जेन जी की मांगों के प्रति सहानुभूति जताने के पीछे यह भी बड़ा कारण है, क्योंकि देश में जेन ज़ी वोटरों की संख्या करीब 25 करोड़ है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस सरकार में मंत्री और शिंदे सेना के नेता संजय शिरसाट को अचानक अभिजीत दिपके के माता-पिता से अपने 'पुराने रिश्तों' की याद आई और आंदोलन समाप्त होते ही वो उनकी कुशल क्षेम पूछने घर जा पहुंचे।

खबर यहां तक उड़ी कि दिपके किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूमिका अदा कर सकते हैं। हालांकि खुद दिपके ने ऐसी कोई बात अभी नहीं कही है। उन्होंने केवल बिहार जाने की घोषणा की है, जहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दिपके के आने का वहां सभी स्तरों पर विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि दिपके महाराष्ट्र से जो हैं, और बिहारियों का मानना है कि महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। इस बीच धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की राजनीतिक गूंज अब अन्य राज्यों में भी सुनाई दे रही है। जिन दस राज्यों में यह मांग उठी है, उनमें से पांच भाजपा और एन एनडीए शासित और चार विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्य हैं। ये राज्य हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। इनमें से तेलंगाना और झारखंड में तो शिक्षा मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास ही है। लिहाजा इस्तीफा उन्हीं से मांगा जा रहा है।

मजे की बात यह है कि विपक्ष शासित राज्यों में यह मांग भाजपा कर रही है तो भाजपा शासित राज्यों में यह मांग विपक्षी पार्टियां कर रही है। लेकिन कोई भी इस्तीफे की मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। धर्मेन्द्र प्रधान से इस्तीफा दिलाने वाली भाजपा भी और उनसे इस्तीफा मांगने वाली विपक्षी सरकारें भी। क्योंकि सभी सरकारें इसे केवल राजनीतिक ब्लैकमेलिंग मान रही है। जबकि इन मामलों में आरोप लगभग वही हैं, जो पेपर लीक विरोधी आंदोलन में लगे थे।

दरअसल सरकारों के जनमत के आगे 'संवदेनशील होकर झुकने' और राजनीतिक दबाव में 'ब्लैकमेल' होने के बीच की लक्ष्मण रेखा बहुत धुंधली है। सरकारें जरूरत से ज्यादा झुकती हैं तो उनका इकबाल धूमिल होता है, नहीं झुकती हैं तो तानाशाह कहलाती हैं। ज्यादातर नागरिक न तो 'अकड़ू सरकार' चाहते हैं और न ही 'कमजोर सरकार' चाहते हैं। जेन जी आंदोलन ने इस विभाजन रेखा को काफी हद तक अधोरेखित किया है। बेशक सरकार को युवाओं की मांगों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन हर कोई धमकाकर सरकार को नमा दे, यह भी देश की राजनीतिक स्थिरता और आत्म विश्वास के लिए ठीक नहीं है।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

अतः इस भूखण्ड में उपलब्ध न होने वाले पदार्थ उस इन्द्रियातीत सूक्ष्म-जगत् में अवश्य विद्यमान हैं जैसा कि परोक्ष ज्ञान के भण्डार वेद में स्पष्टतया लिखा है। ऐसी दशा में किसी भी आस्तिक सज्जन को अब पुराण-वणित अमुक पदार्थ के न मिलने का आक्षेप करने का अधिकार शेष नहीं रहेगा ।

लक्षणा से असम्भवता का परिहार

पौराणिक भूगोल पर दूसरा आक्षेप असम्भवता-विषयक किया जाता है जैसा कि हम पीछे लिख आये हैं। शङ्का वादी महाशयों का कहना है कि दूध दही के समुद्र नहीं हो सकते और नाहीं कोई सोने का पहाड़ हो सकता है। हम प्रतिवादियों के इस आक्षेप का स्वागत करते हुये विनम्र भाव से पूछना चाहते हैं कि- क्या आपके कोश में प्रत्येक शब्द का श्रभिघार्थ ही ग्राह्य होता है?

अथवा प्रसङ्गानुसार लाक्षणिक और व्यंग्य अर्थों को भी किसी हद्द तक उसमें अवकाश मिल सकता है ?

इन्द्रियातीत होने के कारण हम क्या कोई भी यह तो नहीं कह सकता कि उपर्युक्त समुद्रों का और कांचनगिरि सुमेरु का वास्तविक स्वरूप कैसा होगा, परन्तु वेद और पुराण दोनों में ही उनका वर्णन समान रूप से पाया जाता है, इससे यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि उक्त समुद्रों का जल रूप, रस या गन्ध यादि किसी न किसी गुण में दुग्ध दही सुरा आदि पदार्थों से समता अवश्य रखता होगा? जैसे लोक में प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति न्याय के अनुसार किसी एक विशिष्ट गुण के कारण अमुक अमुक पदार्थ का वैसा नाम प्रसिद्ध हो जाता है, इसी तरह साक्षात् दूध दही आदि न होने पर तत्समान जल के कारण उक्त समुद्रों का जैसा नाम प्रसिद्ध हो सकता है।

क्रमशः ...

पंडित रविशंकर शुक्ल

2 अगस्त 1877 को जन्मे रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर जिले में हुआ था, उनके पिता का नाम जगन्नाथ शुक्ला था। रविशंकर शुक्ला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सागर में ही पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की इस दौरान उनके शिक्षा दीक्षा रायपुर जबलपुर और नागपुर से संपन्न हुई। शि क्षा समाप्त करने के बाद 3 साल तक खैरागढ़ राज्य के हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक और बस्तर कवर्धा एवं खैरागढ़ के राजकुमारों के शिक्षक रहे। साल 1906 में रायपुर में वकालत की शुरुआत की। पंडित रविशंकर शुक्ल ने वकालत की पढ़ाई के दौरान ही स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलन के करीब जुड़ चुके थे।

शुरू से पण्डित रविशंकर शुक्ल सार्वजनिक कार्यों पर रूचि रखते थे। लेकिन देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन शुरू होने के दौरान ही उन्होंने वकालत छोड़ कर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। साथी राजनीति के क्षेत्र में भी उतर आए।

उनके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ। राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल और विनोबा भावे जैसे नेताओं से अच्छे संबंध थे। वे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चेतना के संवाहक थे।

आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साल 1930 में पंडित रविशंकर शुक्ल को 3 साल की सजा हुई। उन्हें मध्य प्रदेश के सिवनी जेल और रायपुर के कोतवाली जेल में भी रहना पड़ा। पंडित रविशंकर शुक्ला एक कानूनी विद्वान के साथ-साथ एक उत्कृष्ट अनुभवी नेता थे । वह एक प्रतिबंध लोकतांत्रिक और देशभक्त थे। जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश और समाज के लिए संघर्ष करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था।

पंडित रविशंकर शुक्ला स्वराज पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। सन 1926 से 1937 तक वह रायपुर जिला बोर्ड के सदस्य रहे।1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 4 जुलाई, 1937 ई। को खरे के प्रथम कांग्रेसी मंत्री मंडल में शिक्षा मंत्रि के रूप में सम्मिलित हुए तथा विद्या मंदिर योजनाओं को क्रियान्वित किया। 15 अगस्त, 1947 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1956 तक वे इस पद पर बने रहे। 1 नवंबर, 1956 को नए मध्य प्रदेश के प्रथम संस्थापक मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

सभी को साथ लेकर चलने वाले नेताः पंडित रविशंकर शुक्ल की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में थी, जो मंत्रिमंडल और आम जनता—सबके साथ मिल-जुलकर काम करते थे। वैचारिक मतभेद के बावजूद उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी।

पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और राज्य के लिए समर्पित कर दिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विकास में उनका योगदान ऐतिहासिक है। उन्हीं की स्मृति में रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है।

सीजेपी आंदोलन से सरकार को क्या मिला सबक

सचिन शर्मा

20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद के लिए होने वाले सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) मार्च में हुए बवाल और उसके बाद लगातार उग्र होते युवाओं के तेवर देखकर ठंडी पड़ी केन्द्र सरकार को देखना देश के लिए कोई नार्मल बात नहीं है। सिर्फ छह दिन के अंदर ही कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे समझ आता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस आंदोलन को हल्के तरीके से ना लेने का फीडबैक मिला था। 23 जुलाई की रात 11.52 मिनट पर जब प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर 49 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट करके भारत के GenZ (28 साल तक के युवाओं) को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था कि सरकार पेपर लीक पर त्वरित न्याय की व्यवस्था करेगी, तभी यह तय हो गया था कि शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी समय हो सकता है। हुआ भी ठीक वैसा ही। 25 जुलाई को धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उसी दिन सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ सरकार के प्रतिनिधियों केन्द्रीय मंत्री द्वय जेपी नड्डा और डॉ। जितेन्द्र सिंह ने उनकी सभी मांगे मान लीं और सीजेपी भी अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। 29 जुलाई को लोकसभा से पेपर लीक के खिलाफ बेहद ही कड़ा कानून लोक परीक्षा संशोधन विधेयक% पास हो गया। 30 जुलाई को इस पर राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी। तो क्या सब कुछ अब खत्म हो गया है। पिछले एक सप्ताह से सरकार की तरफ से की जा रही लगातार घोषणाओं और उन पर अमल से देश को क्या पेपर लीक का समाधान मिल गया है। शायद नहीं, दशकों से चल रहे पेपर लीक रैकेट को वश में करना केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए हमेशा से चुनौती भरा रहा है। हरेक बार अंदर का ही कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है। तो वर्तमान केन्द्र सरकार पेपर लीक मसले पर अपनी इस कदर किरकिरी के बाद ऐसा क्या करेगी जिससे देश के युवाओं का विश्वास सरकार के इस सिस्टम पर फिर से बहाल हो जाए। इसी पर चर्चा करते हैं।

19 जुलाई तक सीजेपी आंदोलन साधारण दिख रहा था। सोनम वांगुचक को 18 जुलाई को जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। सरकार को लग रहा था कि आंदोलन की हवा लगभग निकल चुकी है। 20 जुलाई को जब लोग ही नहीं आएंगे तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। 20 जुलाई को जबरदस्त भीड़ उमड़ी। पुलिस और युवाओं के बीच भीषण टकराव हो गया। इसके फोटो और वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उन्हें देखकर युवा डरने के बजाए और भड़क गए। युवाओं की भारी भीड़ जंतर-मंतर और संसद के आस-पास दिखने लगी। इसमें अलग यह था कि युवाओं ने धर्मेन्द्र प्रधान के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अधिक टारगेट किया। अभद्र स्लोगन और रील्स बनाई गईं। युवाओं का आक्रोश इतने कम समय में इतना तेजी से सोशल मीडिया पर फैला कि सरकार हैरान रह गई। देश के सभी कोनों से युवाओं ने सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी कंटेंट डालना शुरू कर दिया। चुनावों को लेकर हमेशा चौकस रहने वाली केन्द्र सरकार के 48 घंटों में ही कान खड़े हो गए। 23 जुलाई की रात में प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम पर सेल्फी वीडियो पोस्ट करना बताता है कि उन्हें रात में जागने वाली जनरेशन को संबोधित करना था। उन्हें यह भी बताया गया था कि ये जनरेशन किसी अन्य सोशल मीडिया हैंडल से कहीं ज्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। उनके वीडियो पर 30 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आए। उन्होंने युवाओं को त्वरित न्याय का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने 24 जुलाई को फिर से कुछ सेकंड का एक धन्यवाद वीडियो पोस्ट किया। 25 जुलाई को धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उनकी जगह पर प्रह्लाद जोशी को नए शिक्षा मंत्री बनाए जाने की घोषणा कर दी गई। अगले ही दिन यानी 26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने फिर से एक वीडियो पोस्ट किया। इस बार एक हाई पार्वड टास्क फोर्स की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि करेंगे। इसमें और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको देश का युवा पहले से ही प्रेरणा स्त्रोत मानता है। इसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ। एस सोमनाथ और आईआईटी मद्रास के निदेशक वी ाकामकोटी हैं। अब सवाल उठता है कि सिर्फ छह दिनों में ही मोदी के ताबड़तोड़ फैसलों के पीछे क्या वजह हैं?

नीट-यूजी पेपर लीक और उसके बाद कई युवा अभ्यर्थियों की आत्महत्या से उपजे रोष को कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक मंच मिल गया। देश भर का युवा इस मंच के साथ हो लिया। जो जंतर-मंतर पहुंच सकते थे वो पहुंचे। जो दिल्ली के आस-पास क्षेत्रों के थे उन्होंने वहीं डेरा डाल लिया। जो दूर के थे वो कई घंटे ट्रेन की यात्रा करके इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचते रहे। यहां तक बात समझ आती है लेकिन पूरे देश के युवाओं ने 20 जुलाई के बाद सीजेपी के आंदोलन का जो समर्थन किया वो अभूतपूर्व था। सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स की बाढ़ सी आ गई। केन्द्र सरकार को तद्रठुं ने निशाने पर ले लिया था। उनके किसी भी बड़े नेता को युवाओं ने नहीं छोड़ा। आश्चर्य की सीमा तब हो गई जब भाजपा और एनडीए के ही कई बड़े नेताओं के बच्चों ने सीजेपी आंदोलन का साथ दे दिया, उनके पक्ष में सोशल मीडिया पर लिखा। असम में एनडीए सरकार के मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत ने केन्द्र सरकार की इस मामले पर तीखी आलोचना की और गुवाहाटी की सड़कों पर उतरकर सीजेपी के पक्ष में प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर (उड़ीसा) से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सारंगी ने खुलकर सीजेपी आंदोलन का समर्थन किया और धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जताई। उल्लेखनीय है कि प्रधान उड़ीसा से ही आते हैं। इसी प्रकार कई अन्य भाजपा नेताओं के बच्चों ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। मामला इतना अधिक उछला कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को कहना पड़ा कि ये जरूरी नहीं है कि जिस विचारधारा का समर्थन माता-पिता करते हों उसी विचारधारा का समर्थन उनके बच्चे भी करें। हालांकि सीजेपी आंदोलन का काउंटर नेरेटिव भी चलाने का प्रयास खूब हुआ। विदेशी फंडिंग, बाहरी और शरारती तत्वों के आंदोलन में शामिल होने वाली थ्योरी भी खूब चली लेकिन भारत का युवा इस आंदोलन को सही मान रहा था।

वर्तमान केन्द्र सरकार को अपनी गलतियों से सबक सीखने वाली माना जाता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में 240 सीटों पर रुकने के बाद भाजपा ने सभी प्रमुख राज्यों के चुनाव जीत लिए। पुराने आंदोलनों की बात करें तो गुजरात में 2015 में आरक्षण को लेकर पटेल आंदोलन से बैकफुट पर आई सरकार ने बाद में उस आंदोलन के सूत्रधार हार्दिक पटेल पर इतना दबाव बनाया कि वो फिर भाजपा में ही शामिल हो गए और आज गुजरात की विरमगाम सीट से भाजपा विधायक हैं। धमेन्द्र प्रधान के 25 जुलाई को हुए इस्तीफे के बाद जब वो 27 जुलाई को संबलपुर (उड़ीसा) के सांसद की हैसियत से संसद पहुंचे और भाजपा सांसदों ने जिस प्रकार से उनका संसद परिसर में स्वागत किया उससे समझा जा सकता है कि पार्टी की नजर में धर्मेन्द्र प्रधान कोई दोषी नहीं हैं। समय आने पर वो मंत्रिमंडल में दोबारा भी शामिल हो सकते हैं। सरकार आगे आने वाले समय में एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय दिखेगी। एक तरफ वो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक और हाई पावर्ड टास्क फोर्स के जरिए एंटी पेपर लीक कानून और शिक्षा सुधार कार्यक्रमों को लागू करके देश के युवाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी और दूसरी तरफ वो भविष्य में ऐसा कोई आंदोलन ना हो इसके लिए भी पूरी व्यूह रचना रचेगी।

आज का इतिहास

1870 टॉवर सबवे, दुनिया का पहला भूमिगत कंदरा मार्ग, लंदन में टेम्स नदी के नीचे खोला गया।

1876 डकोटा टेरिटरी के डेडवुड में एक पोकेरगेम के दौरान अमेरिकी कानूनविद् वाइल्ड बिल हिकॉक की हत्या कर दी गई थी।

1903 आंतरिक मैसेडोनियन क्रांतिकारी संगठन ने मैसेडोनिया में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ इलिंडन विद्रोह शुरू किया।

1905 व्यापारी और दाहिनी ओरिएंट राजनेता ईसाई लुंडबर्ग स्वीडन के प्रधानमंत्री बने।

1922 चीन में एक तूफान से लगभग 60,000 लोग मारे गए।

1923 केल्विन कूलिज संयुक्त राज्य अमेरिका के 30 वें राष्ट्रपति बने वारेन जी हार्डिंग को घातक दिल का दौरा पड़ा।

1934 जर्मनी के नेता एडॉल्फ हिटलर जर्मनी के राष्ट्रपति और चांसलर बने आज जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग के निधन के बाद

1947 ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का विमान अर्जेंटीना एंडीज में माउंट टुपुंगातो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें से मलबे का पता नहीं चल पाया।

1980 इटली के सेंट्रल स्टेशन बोलोग्ना में एक आतंकवादी बम विस्फोट हुआ, जिसमें 85 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए।

1981 मोहम्मद अली राजई को ईरान के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।

1986 स्टूडियो गबिली द्वारा निर्मित पहली फिल्म, हाओ मियाज़ाकी द्वारा निर्देशित कैसल इन द स्काई जापान में जारी की गई।

1990 इराक ने कुवैत पर हमला किया, कुवैत के सैन्य युद्ध के दिनों को पलट दिया और आखिरकार सात युद्ध के बाद खाड़ी युद्ध का प्रकोप बढ़ा।

1999 चीन ने 8000 किमी की लम्बी दूरी तक हमला करने वाली की मिसाइल का परीक्षण किया जो सतह से सतह पर मारने की क्षमता रखती ।

2003 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाइबेरिया में हुवे संघर्ष को रोकने के लिए के लिए सेना भेजने की अनुमति दी।

2004 अमेरिका की लिंडसे डेवनपोर्ट ने रूस की मिस्कीनी की हराकर सान डियागो टेनिस चैम्पियनशिप का महिला एकल खिताब जीत लिया।

2007 पराग्वे की राजधानी आसुनसियोन में एक सुपर बाज़ार में आग लग गयी, जिसमे 300 लोग मरे।

2007 अल कायदा और तालिबान समर्थकों में से दो को पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों पर दोषी ठहराया गया है।

5 अगस्त को क्या बड़ा होने वाला है? डोभाल की एंट्री, गेम सेट

अभिनय आकाश

5 अगस्त की तारीख से पहले देश के सुरक्षा और रणनीतिक चक्रव्यूह में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस हलचल के दो बड़े मायने निकाले जा रहे हैं-पहला यह कि क्या सरकार किसी बहुत बड़े नीतिगत या रणनीतिक कदम की तैयारी में है? या फिर खुफिया इनपुट्स के आधार पर किसी बड़ी चुनौती को नाकाम करने के लिए यह आपातकालीन मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं? इंटेलिजेंस एजेंसियों का अलर्ट और बैठकों की यह रफ्तार बता रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। इस रणनीतिक हलचल का सबसे बड़ा सबूत तब देखने को मिला, जब संसद भवन के अंदर टॉप लीडरशिप की यह महा-बैठक शुरू हुई।

दरअसल, जिस वक्त संसद के भीतर बवाल अपने चरम पर था। विपक्ष के सांसद वेल तक पहुँच चुके थे, ज़ोरदार नारेबाजी हो रही थी और स्पीकर बार-बार शांति की अपील कर रहे थे। एंटी-पेपर लीक बिल पर किसी भी तरह चर्चा आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी और पूरा देश अपने टीवी स्क्रीन पर इस राजनीतिक शोर-शराबे को टकटकी लगाए देख रहा था। लेकिन ठीक उसी पल कैमरे के फ्रेम में एक ऐसी एंट्री होती है, जिसने लुटियंस दिल्ली के बड़े-बड़े सियासी पंडितों से लेकर विदेशी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए! देश के सबसे बड़े जेम्स बॉन्ड—यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बिल्कुल खामोशी से संसद भवन में दाखिल होते हैं। बाहर से देखने पर यह बेहद सामान्य-सी रूटीन विजिट लग रही थी, जिसे सरकारी सूत्रों ने भी सामान्य दौरा ही बताया। लेकिन... जो लोग अजीत डोभाल की कार्यशैली और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं, उन्हें यह समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि इस हंगामे के शोर के पीछे किसी बहुत बड़े, बेहद सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन की फ़ाइल पर मोहर लग रही है!

असल में संसद के वेल में हो रहा हंगामा सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा था। जबकि असल एक्शन संसद भवन के एक बंद कमरे के अंदर चल रहा था। यह कमरा देश के गृह मंत्री अमित शाह का था। जंतर-मंतर पर हुआ हालिया विरोध प्रदर्शन और उसके अंदर भड़की सोची समझी हिंसा के बाद में अमित शाह ने एक मैराथन सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई थी। करीब 40 मिनट तक चली इस हाई लेवल मीटिंग के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के चीफ, केंद्रीय गृह सचिव और

तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल मौजूद थे। इसके तुरंत बाद अमित शाह और अजीत डोभाल की एक एकांत मुलाकात भी हुई।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल शामिल हुए हैं। इनके अलावा बैठक में उपस्थित रहने वाले अन्य मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं। यह बैठक किस विषय पर हो रही है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। नीट के प्रश्नपत्र लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन से पूरा देश दहल उठा था। जनमत के भारी दबाव के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इस माहौल में सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए विपक्ष भी पूरी तरह मताबिभूत है। आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता और दमन का आरोप लगाते हुए विरोधी सांसद लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग भी उठी है। इस पूरे घटनाक्रम से पहले अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 21 जुलाई को कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली चेंज होते हैं और पहली बार दिल्ली की पुलिस की हिस्ट्री में एक आईबी का ऑफिसर पुलिस कमिश्नर बनता है। अचानक दिल्ली में एक आवश्यकता पड़ी ऐसे चीफ की जिसके पास में इंटेलिजेंस का बैकअप है। दिल्ली हमेशा से एक टारगेट रही है आतंकवाद का। क्योंकि जिसने दिल्ली में एक सनसनी पैदा कर दी उसने पूरे भारत को हिला दिया।

डोभाल का वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था। भारत का एजुकेशन सिस्टम और उसके अंदर होने वाली सेंधमारी अब सीधे तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी का मामला बन चुकी है। विदेशी ताकतें और उनके लोकल प्यादे अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर भारत के युवाओं को भड़काना है तो उन्हें उनके भविष्य को लेकर के डरा दिया जाए। पेपर लीक माफिया सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा है बल्कि वो अनजाने में ही देश के भीतर फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का एक ऐसा बारूद तैयार कर रहा है जिससे कोई भी विदेशी टूलकिट एक माचिस की तिल्ली से उड़ा सकती है। दोस्तों युवाओं के अंदर असंतोष फैला करके उन्हें सड़कों पर उतारने की साजिशों को रोकने के लिए यह एंटी पेपर लीक बिल एक ब्रह्मास्त्र की तरह लाया गया है। अखबार

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, हिंसा करना और कानून तोड़ना किसी भी हाल के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दंगाई चाहे किसी भी विचारधारा का हो उसे रियायत नहीं मिलेगी। कोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बाद में सीजीपी के वो नेता जो मंच से सीना ठोक के कह रहे थे कि हम एक-एक प्रदर्शनकारी के ऊपर से केस वापस करवा लेंगे वो अचानक से गायब हो चुके हैं। अब हालात यह हैं कि जोश में आकर के गालियां देने वाले युवा स्टेशनों के चक्कर काट रहे हैं, रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और उनका पूरा करियर दांव पर लग चुका है। उन्हें समझ में आ गया है कि उनके राजनीतिक आकाओं ने सिर्फ अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल किया और अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।

मोदी सरकार और अजीत डोभाल का गेम प्लान सिर्फ सड़क पर पत्थर फेंकने वाले मोहरों तक सीमित नहीं है। असली स्ट्राइक उन लोगों पर हो रही है जो एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठकर के पूरी हिंसा की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। इसी कड़ी के अंदर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यानी कि आईएफएसओ ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने डिजिटल दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। फेसबुक, एक्स, यू-ट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को दिल्ली पुलिस ने सीधा और कड़ा अल्टीमेटम भेजा है। रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस इनपुट इशारा कर रहे हैं कि जंतरमंतर की हिंसा और देश भर के अंदर फैलाए जा रहे फैक्ट नैरेटिव के पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मनी ट्रेल है। करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग के जरिए एक खास इकोसिस्टम इंटरनेट के ऊपर भ्रामक वीडियोस और हेट स्पीच की बाढ़ ला रहा है।

दोस्ती की पिच पर चीन साथ मैच की तैयारी

शशिधर पाठक

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा का प्रयास नई दिल्ली ने तेज कर दिया है। ऐसा हुआ तो 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 भारत और चीन के बीच में मधुरता की राह खोलेगा। शी जिनपिंग 2019 में महाबलिपुरम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संवाद के सात साल बाद यहां होंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि दोनों देशों के एनएसए में तमाम मुद्दों पर सहमति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी दोनों चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच आपसी चिंताओं का समाधान होना चाहिए। 27-28 जुलाई 2026 को विदेश सचिव विक्रम मिस्री बीजिंग के दौरे पर गए थे। मिस्री की यात्रा का मुख्य मकसद भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना, व्यापार, कारोबार के अवसर को बढ़ावा देना, वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयास करना था। इस दौरान विक्रम मिश्री चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग, सीपीसी के अंतरराष्ट्रीय विभाग के मंत्री सुन हैयान, सीपीपीसीसी के उप महासचिव होंग लियांग, ली वेनतांग से मिलकर लौटे हैं। माना जा रहा है कि विदेश सचिव का यह दौरा काफी सफल रहा। 22 जुलाई को फिलीपींस (मनीला) में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष वांग यी से द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों विदेश मंत्रियों की चर्चा में सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने, व्यापार के असंतुलन को तर्कसंगत बनाने, भारतीय बाजार को चीन के बाजार में सम्यक पहुंच बनाने देने, वैश्विक सप्लाई चेन को सरल बनाने, सीधी उड़ानों की बहाली, चीन और भारत के लोगों की आवाजाही बढ़ाकर आपसी विश्वास पर जोर देने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ान सेवा, कैलाश मानसरोवर यात्रा और वीजा नियमों ढील देने के प्रयास हुए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर का कहना है कि भारत और चीन के संबंध पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक हितों की समझ और पारस्परिक संवेदनशीलता से स्थायित्व को पा सकते हैं। 22 जून 2026 को ब्रिक्स एनएसए की बैठक में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी दिल्ली में थे। इस दौरान उनकी अपने समकक्ष अजीत डोभाल से अलग से बात हुई थी। माना जा रहा है कि इस रचनात्मक चर्चा के बाद भारत और चीन के संबंधों में थोड़ी तेजी आने का रोड-मैप बना। ऐसा माना जा रहा है कि अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदल रही भू-राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर भारत-चीन संबंधों पर पारस्परिक जोर देने के पक्ष में है। 2020 में चीन के सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा(एलएसी) के पास भारतीय क्षेत्र में आने की कोशिश की। इस दौरान दशकों बाद हुई हिंसक झड़प में दोनों देशों के सैनिकों को जान गंवानी पड़ी थी। भारत ने इसे चीन के साथ द्विपक्षीय स्तर पर बनी सहमति का उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय नियमों की चीन द्वारा अवहेलना बताया था। यह आपसी विश्वास पर आघात बताया और इसके कारण संबंध बहुत तल्ख हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ केमिस्ट्री ने खूब अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। 2020 में गलवां वैली विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चीन गए थे, लेकिन इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच संवाद, आपसी सहयोग का वातावरण बनाने में काफी बढ़ावा मिला।

राहुल गांधी और विपक्ष को मिलेगी संजीवनी?

प्रभु चावला

राजनीतिक आंदोलनों ने अक्सर सरकारों की दिशा बदल दी है। कुछ आंदोलनों ने सत्ता को उखाड़ फेंका है, कुछ ने नीतियों में उलटफेर किया है, और कुछ ने शक्तिशाली सरकारों को जनता के गुस्से को शांत करने के लिए मंत्रियों की बलि देने पर मजबूर किया है। यही कुछ पिछले दिनों नई दिल्ली में देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल से कहीं अधिक है।

यह 12 वर्षों में पहली बार है कि निरंतर जनआंदोलन, जिसे विपक्ष के लगातार दबाव से बल मिला, नरेंद्र मोदी सरकार में किसी कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे का कारण बना है। सोनिया गांधी और राहुल ने इस्तीफे को 'भारत के युवाओं की जीत' बताया, जबकि भाजपा ने इस व्याख्या को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों के व्यापक हित में काम किया है। इन परस्पर विरोधी राजनीतिक बयानों के बीच महत्वपूर्ण सवाल है- क्या यह इस्तीफा एक सीमित झटका है, या इसने मोदी सरकार द्वारा एक दशक से सावधानीपूर्वक बनाए गए राजनीतिक अजेयता के आभास को परास्त कर दिया है? या इसने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले हतोत्साहित विपक्ष को फिर से सक्रिय कर दिया है?

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा व्यक्ति के लिए कम और एक मिसाल कायम करने के लिए ज्यादा मायने रखता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के पूरे कार्यकाल में यह पहला कैबिनेट रैंक के मंत्री का इस्तीफा है जो जनता के दबाव से लिया गया है। प्रधान का इस्तीफा एक अटूट सिलसिले को तोड़ता है और इसे एक असामान्य तालमेल के माध्यम से हासिल किया गया - राहुल गांधी और कांग्रेस ने धरने और संसदीय व्यवधान का नेतृत्व किया, समाजवादी पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक के क्षेत्रीय सहयोगियों ने उनका साथ दिया, शिक्षण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों की भूख हड़ताल की।

कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक युवा-संचालित विरोध आंदोलन ने उन छात्रों को लामबंद किया जिन्होंने पहले कभी पार्टी की राजनीति में भाग नहीं लिया था। शायद ही कभी किसी एक भाजपाई मंत्री के खिलाफ सड़क का दबाव, संसदीय दबाव और नागरिक समाज का दबाव इतना एकजुट हुआ हो। भाजपा के लिए यहां एक विडंबनापूर्ण स्थिति है। जिस राजनीतिक तौर-तरीके का इस्तेमाल करके कभी भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को घेरा था, आज खुद भाजपा उसी का शिकार बन गई है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, यूपीए के दस साल के कार्यकाल में लगभग आधा दर्जन मंत्रियों ने इसी तरह के दबाव में इस्तीफा दिया था। भाजपा ने वर्षों तक इस घटनाक्रम का उपहास उड़ाते हुए इसे यूपीए के भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का प्रमाण बताया। अब एनडीए ने अपने ही एक मंत्री को ठीक उसी तरह के दबाव के आगे आत्मसमर्पण करवा दिया है, जिस तरह के दबाव से वह कभी खुद के अछूता होने का दावा करता था। लेकिन, क्या इससे विपक्ष को सचमुच मजबूती मिलती है या यह सिर्फ यह साबित करता है कि मोदी सरकार किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, यह एक कठिन प्रश्न है।

एक इस्तीफे से 12 वर्षों का चुनावी वर्चस्व खत्म नहीं हो जाता, और सरकार का अपना तर्क इसके विपरीत एक अलग कहानी पेश करता है: प्रधान ने अपने शब्दों

में 'छात्रों के व्यापक हित में' इस्तीफा दिया, न कि किसी अपराध को स्वीकार करते हुए। मोदी ने परीक्षा प्रणाली में किसी भी गहरी व्यवस्थागत विफलता को स्वीकार नहीं किया है। सीबीआई जांच, परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा कराने को सरकार की हार मानने के बजाय निर्णायक कदम के रूप में सामने आ सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि भाजपा ने इससे कहीं बड़े विवादों का सामना बिना झुके किया है, और एक इस्तीफा, चाहे वह कितना भी प्रतीकात्मक क्यों न हो, राष्ट्रीय विपक्ष को पुनर्जीवित करने का कमजोर आधार है। मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और भाजपा की संगठनात्मक क्षमता, ज्यादातर मामलों में, काफी हद तक बरकरार है। फिर भी, राजनीतिक विश्लेषक इस क्षण को मात्र प्रतीकात्मक नहीं मान रहे हैं। राहुल गांधी के उस करियर में यह पहली ठोस जीत है, जो नारों से अधिक परिणामों से परिभाषित हुआ है।

कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए सबक यह है कि शिकायत की राजनीति जब मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले किसी मुद्दे - जैसे धांधली वाली परीक्षा, छीना गया भविष्य - के साथ जोड़ दी जाए, तो यह अन्यथा प्रभावशाली भाजपा के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकती है। क्या यह आगामी राज्य चुनावों में कारगर साबित होगी?

अब असली परीक्षा उत्तर प्रदेश में होगी, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल पहले ही इन विरोध प्रदर्शनों में राहुल और प्रियंका के साथ खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार अब प्रधान के इस्तीफे को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका असर वोटों पर पड़ेगा या नहीं, यह एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने ऐतिहासिक रूप से बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और योगी आदित्यनाथ के कानून-व्यवस्था के सिद्धांतों को एकल मुद्दों से जुड़ी शिकायतों से अधिक प्राथमिकता दी है, और 2019-20 के नागरिकता आंदोलन और कृषि कानूनों के विरोध जैसे आंदोलनों ने सड़कों पर भारी ऊर्जा तो पैदा की लेकिन चुनावों में भाजपा को सत्ता से नहीं हटा सके।

इतिहास बताता है कि दोनों ही व्याख्याएं एक साथ सही हो सकती हैं। 1974 का जेपी आंदोलन बिहार और गुजरात में अपेक्षाकृत सीमित शिकायतों से शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे इंदिरा गांधी विरोधी राष्ट्रीय लहर में बदल गया और 1977 में उनकी हार का कारण बना। 2011-12 का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी मंत्रियों के इस्तीफों का कारण बना और यूपीए सरकार की नैतिक साख को कमजोर किया, हालांकि इसका सीधा चुनावी लाभ एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, भाजपा को लाभ हुआ क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रधान का जाना इसी तरह की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत हो सकता है। हालांकि यह एक सीमित झटका भी साबित हो सकता है जिसे मोदी सरकार अगले चुनाव चक्र शुरू होने से पहले सफलतापूर्वक बेअसर कर दे।

दिपके, सौरव, रिचा अनजाने में मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं?

नीरज कुमार दुबे

लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है और सत्ता की आलोचना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत मानी जाती है। लेकिन जब विरोध की भाषा शालीनता की सीमा लांघकर व्यक्तिगत अपमान में बदल जाए, जब तर्क और तथ्यों की जगह गाली-गलौज और कटाक्ष ले लें, और जब वरिष्ठों के सम्मान जैसी बुनियादी सामाजिक मर्यादाओं का भी मजाक उड़ाया जाने लगे, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह लोकतांत्रिक विरोध है या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में सभ्य संवाद की संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश है?

हाल के दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके, उसके प्रवक्ता सौरव दास और अभिनेत्री रिचा चड्ढा के बयानों ने इसी बहस को जन्म दिया है। तीनों के बयान अलग-अलग संदर्भों में आए, लेकिन उनकी भाषा और दृष्टिकोण में जो समानता दिखाई देती है वह है व्यक्तिगत कटाक्ष, वरिष्ठों के प्रति असम्मान और मर्यादा की सीमाओं को लांघने की प्रवृत्ति।

अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों के लिए जारी वीडियो संदेश पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार है। यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब प्रधानमंत्री ने परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय बनाने और पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए पारित कानून को विद्यार्थियों के हित में एक

महत्वपूर्ण कदम बताया था। देखा जाये तो कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है, कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठा सकता है या सरकार से जवाब मांग सकता है। लेकिन किसी के व्यक्तित्व या शारीरिक स्वरूप पर टिप्पणी करना क्या स्वस्थ लोकतांत्रिक आलोचना कहलाएगी? क्या इससे छात्रों की समस्या का कोई समाधान निकलता है?

यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी होने के बाद क्या दिपके और उनके सहयोगी इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि अब देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए भी घटिया और व्यक्तिगत भाषा का इस्तेमाल सामान्य मानने लगे हैं? जिस नेता को दुनिया में सबसे अधिक वोट प्राप्त कर लोकतांत्रिक जनादेश मिला हो, उसके साथ असहमति पूरी तरह स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन क्या उसका अपमान लोकतांत्रिक अधिकार की श्रेणी में रखा जा सकता है?

सौरव दास का बयान इस बहस को और गंभीर बना देता है। जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ इस्तेमाल हुई अपमानजनक भाषा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता और लोकतंत्र में जोक को स्वीकार करना चाहिए। देखा जाये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन किसी दिवंगत व्यक्ति या किसी के परिवार के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों का समर्थन करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सार्वजनिक संवाद के स्तर को गिराना माना जायेगा। लोकतंत्र में तीखी आलोचना की पूरी गुंजाइश है, लेकिन व्यक्तिगत अपमान और विशेषकर दिवंगत परिजनों को निशाना बनाना स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं माना जाता।

भारत के मतदाताओं ने बार-बार यह संकेत दिया है कि वे नीतियों पर बहस चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अभद्रता को पसंद नहीं करते। राजनीतिक इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां तीखी व्यक्तिगत टिप्पणियों की तुलना में मुद्दों पर आधारित राजनीति को अधिक स्वीकार्यता मिली। ऐसे में यह मान लेना कि अपमानजनक भाषा ही जनभावना का प्रतिनिधित्व करती है, वास्तविकता से दूर आकलन है।

दूसरी ओर, अभिनेत्री रिचा चड्ढा का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट भी इसी मानसिकता की झलक देता है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा कि केवल उम्र के आधार पर सम्मान नहीं मिलना चाहिए और अपनी बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों और उपमाओं का प्रयोग किया जोकि अपमानजनक और असंवेदनशील थीं। किसी व्यक्ति का सम्मान केवल उम्र से नहीं, उसके आचरण से भी जुड़ा हो सकता है, यह तर्क अपनी जगह है। लेकिन क्या इस विचार को व्यक्त करने के लिए पूरे वरिष्ठ वर्ग का उपहास उड़ाना, उनकी शारीरिक स्थिति पर कटाक्ष करना और उन्हें अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग करना उचित माना जा सकता है? रिचा चड्ढा को यह पता होना चाहिए कि भारतीय समाज में बुजुर्गों का सम्मान केवल परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन का महत्वपूर्ण आधार रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि रिचा चड्ढा इससे पहले भी कई विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं। ऐसे में यह धारणा भी मजबूत होती है कि फिल्म और मनोरंजन जगत के कुछ कलाकार अपनी नई फिल्म या वेब सीरीज के रिलीज़ से पहले चर्चा में बने रहने और लाइमलाइट हासिल करने के लिए जानबूझकर विवादित बयान देते हैं।

देखा जाये तो सरकारों से सवाल पूछना आवश्यक है, आंदोलनों का होना भी लोकतंत्र का हिस्सा है और सार्वजनिक हस्तियों की आलोचना भी पूरी तरह वैध है। लेकिन यदि आलोचना की भाषा ही अपमान में बदल जाए, यदि असहमति की जगह व्यक्ति और उसके परिवार को निशाना बनाया जाए और यदि वरिष्ठों के प्रति सम्मान को ही पिछड़ापन बताने की कोशिश होने लगे, तो यह केवल राजनीतिक या वैचारिक बहस नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक संस्कारों के क्षरण का संकेत बन जाती है।

आंदोलन की हिंसा पर उच्चतम न्यायालय का मत उचित

अवधेश कुमार

उच्चतम न्यायालय का यह मत सर्वथा उचित है कि हिंसा चाहे किसी पक्ष की हो उसकी स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। स्पष्टतः यह एक महत्वपूर्ण पीठ है। प्रचार शक्ति के कारण ऐसा लग रहा है जैसे केवल पुलिस ने एकपक्षीय हिंसा की। पुलिस की ज्यादती है तो उसकी सही तरीके से जांच हो। पर जिस तरह जगह-जगह पुलिस की भी गाडियां तोड़ी गईं, पुलिस पर हमले हुए , पत्रकारों पर हमले हुए, पत्रकारों को घेर कर रखा गया, अनेक के लिए काम करना कठिन हो गया, महिला पत्रकारों तक के साथ हिंसा हुई उन सबकी अनदेखी भविष्य में पूरे देश के लिए खतरनाक साबित होगी। इसलिए उच्चतम न्यायालय का यह मानना बिल्कुल उचित है कि आरोपों से प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बनता है, जिसके लिए एक उच्च-स्तरीय पैनल द्वारा विस्तृत, निष्पक्ष और तटस्थ जांच की जरूरत है। न्यायालय ने केंद्र सरकार के साथ-साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश समेत अन्य संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से उत्तर मांगा है। न्यायपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्त्ताओं के आरोपों से स्वतंत्र जांच का एक शुरुआती मामला बनता है। न्यायालय की यह पंक्ति देखिए, ऐसी जांच में घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंताओं और केंद्र सरकार की दलीलों की भी समान रूप से जांच होनी चाहिए। वैसे न्यायालय ने यह भी आदेश दे दिया कि बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिरासत में लिए गए सभी नाबालिगों और छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही अभी किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई रोकने का भी आदेश दिया है। इसमें तत्काल कोई समस्या नहीं है। कई बार जब समूह हिंसा करने लगता है तो कुछ निर्दोष, निरपराध की मानसिकता भी भीड़ जैसा करने की हो जाती है। हिंसा तो हिंसा है और वह अपराध की श्रेणी में आएगी। बावजूद ऐसे लोग जो वास्तविक छात्र हैं उनके बारे में उदारतापूर्वक विचार होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग या विरोधी भले कुछ कहें लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंडात्मक कार्रवाई की यह सुरक्षा असामाजिक तत्वों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर लागू नहीं होगी। यह स्थिति केवल राजधानी दिल्ली तक सीमित नहीं रही। इसके प्रभाव या परोक्ष रूप से प्रयासों के कारण देश के अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन हुए और चिंता का विषय यह कि हर जगह उग्रता, हिंसा और उद्दंडता उनके भाग बने। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में न्यायालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पक्ष जानने के बाद एक उच्चस्तरीय विशेष जांच दल का गठन कर सकता है। यह उचित भी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और धरना प्रदर्शन के नाम पर हिंसा तथा अन्य अपराध करने वालों को सजा नहीं मिली तो इससे ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ेगा जिन्हें भविष्य में संभलना कठिन होगा। इसीलिए हिंसा के हर संभव सबूत यानी जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग, वायरलैस संचार रिकॉर्ड, पी.सी.आर. कॉल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान बैंच ने इस बात पर जोर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। साथ ही यह भी माना कि दोनों पक्षों की ओर से की गई हिंसा की समान रूप से जांच होनी चाहिए। संविधान के अंतर्गत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जायज है और इसे सुरक्षा भी प्राप्त है। किंतु अगर ऐसे विरोध प्रदर्शनों में खास झंडे वाले घुसकर सह मेजबान बन जाएं और अपराध करें तो इन सब की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ध्यान रखिए, पुलिस कार्रवाई से लेकर केंद्र सरकार और राज्यों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनेक नामी वकील खड़े थे। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। न्यायालय ने सबकी सुनने के बाद कहा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनसे कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। तो न्यायालय का मत बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई निर्दोष निरपराध फंसे नहीं लेकिन दोषी, अपराधी, षड्यंत्रकारी कानून के शिकंजे से बचें भी नहीं। नीट का प्रश्न पत्र लीक हो या किसी परीक्षा का यह सबके लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है। मनुष्य के विरुद्ध छात्रों और विभागों और आम लोगों के अंदर क्षोभ बिल्कुल स्वाभाविक है। इनके लिए जिम्मेदार और संलिप्त लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो उदाहरण बने।

गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र और देवी सरस्वती हैं। यदि शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार इसका जाप किया जाए, तो मां सरस्वती प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है...

वेदमाता गायत्री

गायत्री शब्द का अर्थ है प्राणरक्षक। 'गाय' कहते हैं प्रण को तथा 'त्री' का तात्पर्य है त्राण संरक्षण करने वाली। अत: जिस शक्ति से प्राण का, प्रतिभा का व जीवन का संरक्षण होता है, उसे गायत्री कहते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से गायत्री के चार भागों का व्याख्यान चार वेदों के रूप में किया था। इसी कारण गायत्री को वेद माता कहते हैं। यह गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति, धर्म एवं तत्वज्ञात का बीज है।

त्रियदा गायत्री

गायत्री वैदिक संस्कृत का एक छंद है, जिसमें आठ-आठ अक्षरों के तीन चरण कुल 24 अक्षर होते हैं। 'ॐ भूर्भुव: स्व:' यह गायत्री का शीर्ष कहलाता है। शेष आठ- आठ अक्षरों के तीन चरण हैं। इन्हीं तीन चरणों के कारण गायत्री को त्रियदा कहा जाता है। एक शीर्ष तथा तीन अन्य चरण इस प्रकार उसके चार भाग बने। इन चारों चरणों का रहस्य ही वेदों में वर्णित किया गया है।

मंत्र का भानार्थ

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि। धियों योनः प्रचोदयात्

प्रत्येक वेदमंत्र के प्रारंभ में ॐ का प्रयोग किया जाता है। ॐ कार ईश्वर का द्योतक है। गायत्री मंत्र में भी ॐ कार का प्रयोग इसी कारण से हुआ है। 'भू:भुवस्व:' यह तीन लोक हैं। अध्यात्म में भू: स्थूल शरीर के लिए, भुव: सूक्ष्म शरीर के लिए तथा स्व: कारण शरीर के लिए प्रयु त किया गया है। बाहरी जगत और अंतर के तीनों लोकों में ॐ कार अर्थात ईश्वर सर्वव्याह्रश्वत है। व्याहतियों में इसी तथ्य का प्रतियादन है। 'तत्' का अर्थ है वह। 'सवितु' का भावार्थ है- प्रकाश तथा ऊर्जा से ज्ञात तथा वर्चस से ओतप्रोत परमेश्वर।

'वरेण्य:' का भावार्थ है श्रेष्ठ, तेजस्वी, विनाशक, देव। इन चार श दों में परमब्रह्म परमात्मा के उन गुणों का वर्णन है, जो अध्यात्मवादी अपनाने का प्रयत्न करते हैं। भर्ग शब्द तेजस्विता का बोधक है। इस शब्द में प्रतिभा साहसिकता, तत्परता, तन्मयता जैसे तत्वों का समावेश है। भर्ग का एक भाव नष्ट करना भी है। अनैतिकता, अवांछनीयता जैसी दुष्प्रकृतियां अगर मनुष्य को घेरे रहें, तो मनुष्य माया व पतन के गर्त में फंस जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए ऐसी प्रखरता का उद्भव होना चाहिए, जो अंतर के कष्टों तथा भीतर के कल्मषों से छुटकारा दिला सके।

सविता, वरेण्यं, भर्ग के उपरांत चौथी विभूतिमत्रा का नाम है देव। ईश्वर को देव श द से संबोधित करने का मतलब यह है कि हम ईश्वर के परम भक्त बनें तथा उसके देवत्व की विशेषता में अनुगमन करें।

'धीमहि' शब्द का अर्थ है धारण करना। आदर्शों को व्यवहार में उतारना ही उनकी धारणा है। ईश्वर दयावान, सदा प्रसन्न चित्त, धैर्यवान, क्षमावान व सदा आनंदित रहने वाले हैं। सुख-दुख से निरलेप हैं। उनके इन्हीं गुणों को धारण करना चाहिए। प्रथम चरण में सविता तथा वरेण्यं की तथा द्वितीय चरण में भर्ग तथा देव की अवधारणा का प्रशिक्षण है। गायत्री के अंतिम तृतीय चरण 'धियों यो न: प्रचोदयात्' के अंर्तगत परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि साधक अकेले नहीं, बल्कि समस्त जन समुदाय में, प्राणिमात्र में 'धी' तत्व की वृद्धि करे। 'न:' हम सबको और 'धिय:' वृद्धियों को कहते हैं, इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि अपनी अनुग्रह वर्षा करें।

उपासना का उद्देश्य

गायत्री उपासना का उद्देश्य है व्यक्ति में ऐसे तत्व का विकास करना, जिससे उस पर परमात्मा की कृपा हो सके। गायत्री मंत्र के जाप से दैविक व भौतिक साधनों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। उपजाऊ भूमि में ही वर्षा के बादलों के अनुग्रह से हरियाली उपजती है। कठोर चट्टानों पर तो एक पत्ता भी नहीं उगता। गायत्री उपासक अपना पूरा ध्यान आत्मपरिष्कार में लगाता है। गायत्री मंत्र के प्रभाव स्वरूप मनुष्य तामसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर परमपिता परमेश्वर से एकीकार होने के मार्ग पर अग्रसर होता है।

उपासना की विधि

- स्नानाआदि से निवृत होकर सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके गायत्री मंत्र का जाप करने से बुद्धि ते ा होती है।
- पुष्प व मीठा नेवेद्य अर्पित करके ऊनी या कुशासन पर बैठकर तुलसी या रूद्राक्ष की माला पर जाप करें।
- गायत्री मंत्र धर्म व अर्थ दोनों की वृद्धि करने वाला है।
- जाप करने से शरीर आरोग्य रहता है। काया के कष्ट मिटते हैं।
- लगातार जाप करने से मोक्ष की प्राह्रिश्वत होती है
- विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे याददाश्त बढ़ती है तथा माता सरस्वती की कृपा से ज्ञान में वृद्धि होती है।

दुख नाशक चौपाइयां

संपदा प्राप्ति के लिए
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं
सुख संपति नाना विधि पावहि।

आमदनी के लिए
विश्व भरन-पोषन कर जोई
ताकर नाम भरत अस होई

कार्य विध्न हरण के लिए
सकल विघ्न व्यापहिं नाहिं तेही
राम कृपाकर चितवहिं जेही।

संकट नाश के लिए
दीन दयाल विरद संभारी
हरहु नाथ मम संकट भारी

रोग शांति के लिए
दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज काहु नहिं व्यापा

ग्रह शांति के लिए
नाम प्रभाउ जान सिव नीको
कालकूट फलु दीन अमी को

मनोकामना पूर्ति के लिए
सुनु सिय सत्य असीस हमारी
पूजहिं मनकामना तुम्हारी।

रक्षा कवच के लिए
मामभिरक्षय रघुकुल नायक
घृत वर चाप रुचिर कर सायक।

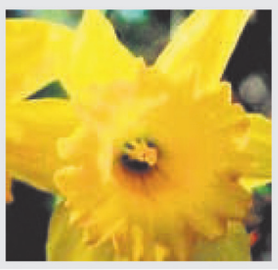

चिली खाने से उग्र होगा मंगल

रसोई अग्नि का स्थान है, मंगल अग्नि का ग्रह है इसलिए मंगल का वास रसोई में होता है। इसके साथ ही मिर्च,मसाला, गैस, कैरोसीन, छुरी, कांटा, स्टील के बर्तन, नमक, सूखे मेवे, प्याज व लहसुन इत्यादि भी मंगल के अधीन हैं।

जिस घर में अधिक मिर्च-मसाले वाला भोजन बनता हो या फिर मिर्च-मसाला अत्याधिक मात्रा में इस्तेमाल होता हो तो इससे यह समझा जा सकता है कि यहां मंगल की उग्रता अधिक है। मंगल को शांत करने के लिए मिर्च-मसाले का भोजन में प्रयोग बहुत ही संतुलित मात्रा में करना चाहिए।

अधिक मसाले व तीखे भोजन की वजह से उग्र मंगल अग्निभय, फूड प्वाइजनिंग, जख्म, दुर्घटना इत्यादि तक करा सकता है।

यह तो हुई वास्तु की बात, मगर ज्योतिष में किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति देख कर उसे वास्तु संबंधी उपाय बताए जाते हैं और वे उपाय बड़े कारगर होते हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर है या नीच का है तो उसे रसोई में बैठ कर भोजन करना चाहिए। इससे उसके कमजोर मंगल को ताकत मिलेगी। इससे जातक मंगल से

होने वाले नुक्सान से बच सकेगा। मंगलधैर्य, क्रियाशील, रचनात्मक क्षमता और अधिकार देने वाला ग्रह है। यदि रसोई के ठीक बगल में शौचालय है तो यह स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि शौचालय में राहु का वास होता है इससे मंगल और राहु एक साथ हो जाते हैं।

राहु और मंगल के साथ होने से फूड प्वाइजनिंग और चोट-चपेट लगने का भय रहता है। एक बात यह भी देखीगई है कि अगर कुंडली में मंगल गड़बड़ स्थिति में हो तो उस जातक के घर के रसोई भी गड़बड़ होती है। गलत रसोई में में बनाया गया भोजन खाने के बाद एसिडिटी और पेट के रोग अधिक होने की आशंका रहती है। रसोई में डस्टबिन की सफाई बहुत जरूरी है। चूंकि कूड़ा राहु के अंतर्गत आता है इसलिए मंगल के स्थान पर राहु की वस्तु रखना टीक नहीं है। समय-मसय पर रसोई से कूड़ा हटाते रहना चाहिए। कभी भी रसोई घर में झाड़ू नहीं रखना चाहिए।

घरों में पत्थर लगाने का चलन बहुत बढ़ गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पत्थर नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं...

घर में पत्थर लगा हो तो...

पत्थर के बने मकान, दीवार या स्टोन पिलर का प्रतिनिधित्व म 'गल ग्रह करता है। शनि और राहु ग्रह मंगल के शत्रु होते हैं। ऐसे में निश्चित समझना चाहिए कि जब शनि दुश्मन बना हुआ हो, तोऐसे मकानों में रहने वाले या उपयोग में लेने वाले सुखी रह ही नहीं सक ते। उसी प्रकार छाया ग्रह राहु भी वहां रहने वालों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। यदि ऐसे पत्थरों से बने मकानों में अंधेरा हो, तो वहां भूत-प्रेत निवास करना पसंद करते हैं या यूं कहे कि ऐसे घरों में इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि वहां भूत-प्रेत होने का अहसास होता है। एक बात याद रखनी चाहिए, अगर कोई आदमी वास्तु के अनुसार बने भवन में रहता है, उसके ग्रह निर्बल हों, तो भी उसका जीवन सामान्य ढंग से सुख-शांति से व्यतीत होता है।

पत्थर अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और मिट्टी बुध का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में पत्थर अहंकारी बनाता है और मिट्टी धार्मिक पवित्रता प्रदान करती है। वे मकान, जिन्हें पत्थरों को मिट्टी से जोड़कर बनाया जाता है, वहां बुध और मंगल के प्रभाव का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। यदि किसी घर के सामने पत्थर का बना आशियाना हो, तो उस घर में रहने वाला परिवार कभी भी किसी भी तरह तरक्की नहीं कर सकता। उनके बच्चों को पढ़ाई में बहुत विघ्न, बाधाएं आती हैं। यदि पत्थरों से बना आशियाना पुराना, क्षतिग्रस्त या टूटा-फूटा हो, तो उसमें रहने वालों के साथ-साथ आसपास के घरों में रहने वाले भी अभाग्य का शिकार होते हैं।

यदि किसी घर के ठीक सामने कोई बड़ा पत्थर या स्टोन पिलर हो, उस घर का मुखिया लड़ाई-झगड़ा पसंद करने वाला, आगे बढ़कर दुश्मनी मोल लेने वाला होता है। यदि कोई बड़ा पत्थर घर के मुख्यद्वार के एकदम सामने आता हो, ऐसे घर में रहने वाले दंपत्ति के आपसी संबंधी सौहार्दपूर्ण नहीं रहते। किसी घर में बड़ा पत्थर हो या बड़े पत्थर का बना कोई स्लैब हो या घर के सामने छोटी पहाड़ी हो, ऐसी स्थिति में उसका मुखिया उसके बच्चे भय में रहते हैं। कई

वास्तु शास्त्र

मकान बहुत सुंदर बनाए जाते हैं, पर बचत के लिए मकान और चारदीवारी के बीच में पत्थर के स्लैब लगाए जाते हैं। ऐसे घरों में रहने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय और व्यापार में भी सफलता नहीं मिल पाती।

यदि कोई भवन या उसकी कंपाउंड वाल पत्थरों से बनी हो, तो इस दोष को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि उसे सीमेंट या मिट्टी से ढंक देना चाहिए अर्थात प्लास्टर कर देना चाहिए।

उपाय शनि देव के

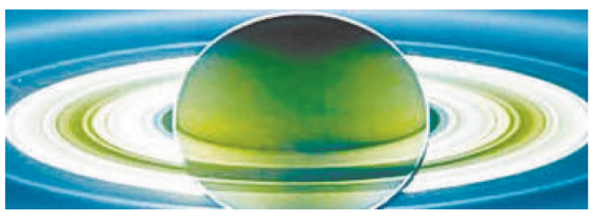

जन्म कुंडली में यदि षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादश शेष हों या द्वितीयेश-सप्तमेश होने के कारण मारकेश हों तो कष्टकारक होते हैं। व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतर्दशा या अशुभ गोचरीय परिभ्रमण ढय्या-साढ़ेसाती के समय प्रतिकूल फल देते हैं। इससे बचने के लिए आप इनमें से कोई एक उपाय कर लें। इससे अशुभ फलों में कमी आएगी-

- काले घोड़े की नाल की अंगूठी दायें हाथ की मध्यमा अंगुली में पहनें या काले कुत्ते को सायंकाल रोटी खिलाने से भी लाभ मिलेगा।
- शनिवार को शनि स्त्रोत का पाठ करें। शनिवार का व्रत भी रखें तो ज्यादा अच्छा है।
- शनि के वैदिक मंत्र (शन्नौदेवीरभिष्टयादि) या तांत्रिक मंत्र (ऊं प्रां प्रीं प्रौं स: शनये नम:) की दो माला प्रतिदिन जपें।
- शनिवार को पीपल के वृक्ष को सींचें, वृक्ष यदि मंदिर परिसर में हो तो ज्यादा अच्छा है।
- हनुमान जी की पूजा-अर्चना करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकाण्ड का पाठ या हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। शनिवार या मंगलवार का व्रत कर सकते हैं।
- शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार समय-समय पर करें। (काले तिल, उड़द, कुलथी, खाद्य तेल, व ाला वस्त्र, छात्रा कम्बल, जूते-चप्पल, लोहे की वस्तुएं, स्टील के बर्तन आदि)।
- काले या गहरे नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग यथासंभव नहीं करें। शनि की वस्तुओं का दान ग्रहण नहीं करें।
- सूर्य को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें।
- कोई नया कारोबार, जोखिम वाला काम, ज्यादा रकम का इन्वैस्टमेंट आदि नहीं करें।

इसके अतिरिक्त सात्विक आहार-विहार, विनम्र व्यवहार, क्रोध पर नियंत्रण, लोभ-लालच से परहेज, अच्छी संगति, सकारात्मक विचार, परोपकार, शरीर और मन की पवित्रता, ईश्वर भक्ति स्वाध्याय आदि से समस्त ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं जिनमें शनि भी शामिल है।

आपकी कार का रंग

यदि आप कार खरीदने जा रहे हैं, तो उसके रंग का चयन अपनी शुभता के अनुसार करें। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पर पड़ने वाले ग्रह योगों से आप अपने वाहन के रंग के बारे में जान सकते हैं।

आपके वाहन का रंग किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय करने के लिए चतुर्थ भाव एवं चतुर्थेश पर जिस ग्रह का प्रभाव हो, उससे संबंधित ग्रह के अनुसार वाहन के रंग का निर्णय करें। यदि सूर्य या मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव एवं चतुर्थेश पर प्रभाव हो, तो लाल रंग का वाहन यदि चंद्रमा एवं शुक्र का प्रभाव चतुर्थ भाव एवं चतुर्थेश पर हो, तो हरे एवं आसमानी रंग का वाहन, यदि गुरु का प्रभाव वाहन से संबंधित भाव एवं भावेश पर हो, तो पीले रंग का वाहन, यदि शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव एवं चतुर्थेश पर युति अथवा दृष्टि के द्वारा हो, तो नीले गहरे रंग वाली कार लें। चंद्र एवं शुक्र के प्रभाव के साथ ही अन्य ग्रह का प्रभाव होने पर वाहन का रंग हल्का एवं चमकीला लें।

अंतरदशाओं से ज्वर

ज्वर (बुखार) के कई भेद व उपभेद हैं। यह व्याधि सामान्य होती है, किंतु परिणाम कई बार भयावह हो जाते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध व शनि ज्वर के प्रमुख कारक ग्रह हैं। नीच के सूर्य व नीच के ही चंद्रमा की महादशा में या केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा अथवा शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा में बुखार या ज्वर भयानक रूप ले लेता है।

ज्योतिषीय कारण : गुणाकर, वराहाचार्य, श्रीपति आदि ने माना है कि सूर्य, चंद्र एवं बुधशनि प्रधान रूप से ज्वर के कारक ग्रहों में होते हैं। नीचस्थ सूर्य व नीचस्थ चंद्र की महादशा में अथवा केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा या शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा हो तो जातक बुखार से जकड़ जाता है।

कौन सा ज्वर : ज्योतिष का मत है कि लग्नेश व षष्ठेश सूर्य युक्त हो तो जातक को ज्वर का भय होता है। षष्ठ व अष्टम में सूर्य हो या अष्टम में चंद्रमा राहु युक्त हो, अष्टमेश चंद्र या राहु या केतु युक्त हो तो तो चौथिया (चार दिन के अंतराल वाला) ज्वर होता है। लग्न

में मंगल व अष्टमेश में सूर्य हो तो दाह ज्वर होता है। चंद्रमा शीत कफ ज्वर, बुध पित्त ज्वर व शनि वात ज्वर के कारक ग्रह हैं।

अनुभूत कारण : निरंतर या आए दिन ज्वर से पीड़ित रहने वाले कई जातकों की कुंडलियों में देखा गया है कि जब उनके राहु में बुध की अंतरदशा चली तो वह बुखार, टाइफाइड व अन्य ज्वरों से लगातार परेशान रहा और आर्थिक तथा घरेलू मुश्किलों से त्रस्त हो गया।

ज्योतिषीय उपचार : जातक की कुंडली व दशा-अंतरदशा पर विचार करने के बाद जिस ग्रह के कारण ज्वर हो रहा हो, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान और मंत्र जाप आदि करना चाहिए। जातक स्वयं करे तो बेहतर और यदि किसी कारण से स्वयं नहीं कर सके तो घर का अन्य व्यक्ति उसके नाम से दान व मंत्रों का जाप कर सकता है। ज्वर पीड़ित के कक्ष में निरंतर गुग्गुल की धूप और संबंधित ग्रह की मंत्र ध्वनि लाभकारी होती है।

सुंदर के साथ शुभ भी होते हैं निशान

बाएं पैर की पहली और आखिरी उंगली फड़के तो आपको लाभ होगा। दाएं पैर की उन्हीं उंगलियों का फड़कना अशुभ होता है। पांव की पिंडली शनि और बुध नक्षत्र के अधीन आती है। इसके फड़कने से काम में बाधा आती है और यह शत्रु के पैदा होने का संकेत है। दायां घुटना फड़के तो अशुभ और बायां फड़के तो शुभ होता है।

बायां पांव फड़कना : शुभ होता है। दायां पांव फड़कने से मुसीबतों का अंत होता है। बाईं जांघ के फड़कने से दोस्त से सहायता मिलती है, जबकि दाईं जाँघ फड़कने से शत्रु शांत होते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा फड़कने से शुभ समाचार मिलता है, जबकि बायां फड़के तो नुक्सान होता है।

शरीर के तिल या मस्से : उनका संबंध शनि व राहु से माना जाता है। शनि धीरे-धीरे फल प्रदान करता है और राहु अचानक ही शुभ या अशुभ फल दे देता है।

दाएं गाल पर तिल : शुभ होता है। ठुड्डी पर तिल प्यार में कमी का सूचक है।

दाईं आंख पर तिल : खूब प्यार मिलता है। बाईं आंख पर तिल होने से प्यार में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भौंहों पर तिल होने से घूमने-फिरने के मौके मिलते हैं। बांह पर तिल होना हमेशा शुभ माना जाता है। गाईं बांह पर तिल हो तो अपार धन मिलता है। बाईं तरफ हो तो धन के साथ-साथ पुत्र की प्राप्ति होती है। होंठ पर तिल व्यक्ति के लालची स्वभाव दर्शाता है।

गले पर तिल : ऐसे जातक की धार्मिक कार्यों में अधिक रूचि होती है। कान पर तिल होने से धन मिलता है। गर्दन पर तिल आलस्य की निशानी है। अंगूठे पर तिल उत्तेजना की निशानी है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से तेज मिजाजा का होता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

साल 2020 दिल्ली दंगे में ताहिर को उम्रकैद

नईदिल्ली। साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान ड्यूक अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में 13 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था. दोषी ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को अदालत ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई.सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह बेहद गंभीर घटना थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह ऐसा मामला था जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया. अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह पूरी घटना सामने आई, उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया. सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी।

आकाश नहीं मैं तय करूंगी विधानसभा टिकटः मायावती

लखनऊ। मायावती के भतीजे आकाश आनंद यूपी के सियासी रण में उतरने जा रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने अपनी भाषण शैली से देशभर का ध्यान खींचा था. इसके बाद बीएसपी समर्थकों में उत्साह भी देखने को मिला था. आकाश आनंद ने आक्रामक अंदाज में बीजेपी, सपा और कांग्रेस, तीनों पर निशाना साधा. वहीं, मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव अब नजदीक आ रहा है, जिसकी तैयारी के लिए मेरे द्वारा खुद प्रदेश की पिछली कई राज्य स्तरीय बड़ी बैठकें लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ली गई हैं. इनमें पार्टी के उम्मीदवार तय करने के लिए खासकर प्रदेश व मंडल स्तरीय पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. मायवती ने बताया है कि इसके तहत अभी तक मेरे द्वारा उनका इंटरव्यू आदि लेकर लखनऊ में लगभग दो दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं।

गालियां देने वाले बच्चों को मैं माफ करता हूंः पीएम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर बड़ा मैसेज दिया. रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए और जेन-जी को संबोधित किया. उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं. पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड्स. आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं. जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोलीं, किसी भी सभ्य समाज को शोभा ना दे. ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, मुझे तो गालियां दी गईं, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गईं. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था. लेकिन, मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है. इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं।

सेना ने मार गिराया पाकिस्तान का चाइनीज ड्रोन

नईदिल्ली। भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के खौर सेक्टर में पाकिस्तानी निगरानी ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया है. यह घटना चकला गांव के पास हुई, जहां ड्रोन महत्वपूर्ण रक्षा ठिकानों के करीब मंडरा रहा था. सेना के अनुसार यह ड्रोन चीन में बना है. इसे निगरानी मिशन के लिए बदला गया था. ड्रोन के साथ 64 जीबी माइक्रो एसडी कार्ड भी बरामद किया गया है. जांच में पाया गया कि कार्ड में भारतीय सेना के संवेदनशील स्थानों के फुटेज मौजूद हैं. सुरक्षा एजेंसियां घटना की गहराई से पड़ताल कर रही हैं. यह घटना भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन आधारित जासूसी की बढ़ती चुनौती को फिर से उजागर करती है. खौर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्थित है. यहां सुरक्षा व्यवस्था हमेशा सतर्क रहती है. जब ड्रोन को महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों के आसपास देखा गया तो सेना ने तुरंत कार्रवाई की और उसे नीचे गिरा दिया. बरामद ड्रोन को चीन में बना है।

बिहारः एमएलसी देवेश कुमार ने दिया इस्तीफा

बिहार। पटना में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि उनकी खाली हुई सीट पर मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जा सकता है.

पटना में बीजेपी ने एक बड़े सियासी घटनाक्रम के बीच अपने विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार का इस्तीफा करा दिया है. देवेश कुमार ने अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया. उनके इस्तीफे के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर हो रही है. माना जा रहा है कि देवेश कुमार की खाली हुई विधान परिषद सीट पर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जा सकता है. दरअसल, मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हुई है. ऐसे में देवेश कुमार का अपनी विधान परिषद सीट से इस्तीफा देना बेहद अहम माना जा रहा है. इस कदम के बाद दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजे जाने का रास्ता खुल सकता है और उनके मंत्री बने रहने को संवैधानिक सुरक्षा देने की कोशिश की जा सकती है।

पीएम मोदी ने भोगपुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री ने करीब 18 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया

विशाखापत्तनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आज का दिन आंध्र प्रदेश के विकास और स्वर्ण आंध्र के विज़न के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि यहां लगभग 18,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, उनका उद्घाटन किया गया है और उनकी आधारशिला रखी गई है। ये विकास कार्य उस तेज़ रफ़्तार का प्रतीक हैं जिससे आंध्र प्रदेश आज तरक्की कर रहा है।

मोदी ने आगे कहा कि चंद्रबाबू की एक खासियत यह है कि उन्होंने इन दोनों ही पहलुओं को अपनाया है। एक तरफ़ आसमान छूने वाली सुविधा यानी एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ़ हमारी आदिवासी बहनों द्वारा धिमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू की इस सोच की विशेष रूप से सराहना करता हूँ। आज, उसी धरती पर जहाँ अल्लूरी सीताराम राजू ने अपना जीवन आदिवासी कल्याण के लिए समर्पित किया था, आंध्र प्रदेश में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन हो रहा है। यह हवाई अड्डा आंध्र और उत्तर आंध्र क्षेत्र के विकास के लिए एक रनवे का काम करेगा। यह आंध्र के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लॉन्चपैड है।

मोदी ने कहा कि पहले एयरपोर्ट्स के नाम अक्सर एक ही परिवार के नाम पर रखे जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि और पंजाब के एयरपोर्ट का नाम संत रविदास के नाम पर रखा। केंद्र की एनडीए सरकार ने तय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने

कहा कि इन बारह वर्षों में सिर्फ़ एयरपोर्ट्स की संख्या ही नहीं बढ़ी है। हमारी उड़ान योजना की वजह से, गरीब परिवारों के लोगों को भी हवाई यात्रा करने का मौका मिल रहा है... हाल ही में सरकार ने उड़ान योजना का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसके लिए 29 हज़ार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा भोगपुरम एयरपोर्ट इस साल चालू होने वाला देश का दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट ने 15 जून को कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस एयरपोर्ट को एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया है। इसका मकसद उत्तरी आंध्र में औद्योगिक विकास, रोज़गार पैदा करने, एक्सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च को बढ़ावा देना है। 2,200 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट को जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके विकसित किया है।

यह बड़ा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2,703.26 एकड़ में फैला है। इसमें 2,203.32 एकड़ में फैला एयरपोर्ट, 500 एकड़ का एविएशन हब और 136.63 एकड़ में फैली एविएशन यूनिवर्सिटी और एडुसिटी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट और अप्रोच रोड भी शामिल हैं। जीएमआर ग्रुप ने बताया कि एयरपोर्ट का काम तय समय से कई महीने पहले ही पूरा हो गया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 हैं। एक समय था, जब हवाई उड़ाने सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित थी, एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ-जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश ब्लू इकॉनमी को लगातार मजबूत कर रहा है। हमारा विजन है कि ये पूरा क्षेत्र तटीय आर्थिक गलियारा के रूप में विकसित हो। इसी लक्ष्य के साथ, विशाखापट्टनम से कृष्णापट्टनम तक... हमारे पुराने बंदरगाहों को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा मुलापेटा और रामायापट्टनम में हम नए बंदरगाह भी बना रहे हैं।

उद्घाटन के दौरान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी दी।

सीएम नायडू ने भोगपुरम में मोदी की जमकर तारीफ की

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि उसे एक परखी हुई लीडरशिप मिली है, जबकि कई लोकतांत्रिक देश लीडरशिप के संकट का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले भोगपुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि हर जगह लोकतांत्रिक देश नए नेताओं की तलाश में संकट का सामना कर रहे हैं। भारत खुशकिस्मत है। यहाँ एक परखी हुई लीडरशिप है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर पच्चीस सालों में नरेंद्र मोदी जी ने असाधारण काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जिनमें देश को आगे ले जाने का विज़न और काबिलियत है।

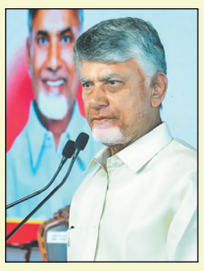

नायडू ने कहा कि लोकतांत्रिक दुनिया में वे अकेले ऐसे नेता हैं जिनके पास ज्ञान, टेक्नोलॉजी और 144 करोड़ लोगों को साथ लेकर देश को आगे ले जाने की काबिलियत है। इस पर लोगों ने मोदी, मोदी के नारे लगाए। डिजिटल इकॉनमी में भारत की तरक्की का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने डिजिटल पेमेंट के मामले में देश की लीडरशिप का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांज़ैक्शन अमेरिका या चीन में नहीं, बल्कि भारत में हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यही किया है। इससे पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नायडू और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला विक्टिम कार्ड खेलने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन युवाओं को माफ करने की बात कहकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अपशब्द कहे थे। विपक्षी पार्टी ने मांग की कि प्रधानमंत्री प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई बर्बर कार्रवाई और पेपर लीक के कारण युवाओं को हुई परेशानी के लिए माफी मांगें।

विपक्षी पार्टी ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम सभाएं अब किसी को प्रभावित नहीं कर रही हैं। उन्होंने इसे अत्यधिक आत्ममुग्धता का उदाहरण बताया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, शुक्रवार देर रात प्रधानमंत्री ने अत्यधिक आत्ममुग्धता दिखाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे युवाओं को माफ कर दिया। यह देश और युवाओं का अपमान है। हमारी सरकार के दौरान परेशानियां झेलने वाले युवा उनसे माफी की मांग करने का पूरा अधिकार रखते हैं। प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम सभाएं अब किसी को बेवकूफ नहीं बना रहीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात का दुख है कि जंतर-मंतर पर उनकी दिवंगत मां को भी अपशब्द कहे गए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी बेटियों ने भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने भटके हुए बच्चों को माफ करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह समाज में मौजूद पीड़ा को समझते हैं, लेकिन यह समय युवाओं को सही रास्ता दिखाने का है।

जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में कहा, खुद को गैर-जैविक बताने वाले प्रधानमंत्री को विक्टिम कार्ड (खुद को पीड़ित

दिखाना) खेलना पसंद है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करते हैं।

रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री उन्हें बदनाम करने के लिए अक्सर झूठ फैलाते हैं। वह ऐसा सिर्फ सार्वजनिक भाषणों में ही नहीं, बल्कि संसद में भी करते हैं। वह संसद के अंदर और बाहर अपशब्दों का इस्तेमाल करने वालों की पूरी फौज को बढ़ावा देते हैं और उन्हें पूरा संरक्षण देते हैं।

रमेश ने कहा, पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री पेपर लीक के मामलों और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कार्रवाई से लाखों युवाओं को हुई परेशानी के लिए माफी मांगें।

उन्होंने आगे कहा, पूरा देश राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावा चोरी, आस्था धोखा मामले पर प्रधानमंत्री से माफी का इंतजार कर रहा है। इसी ट्रस्ट की घोषणा उन्होंने 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में की थी। पूरा देश 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के लिए भी प्रधानमंत्री से माफी की उम्मीद कर रहा है।

कांग्रेस का आरोप है कि नोटबंदी से करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई और लाखों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बंद हो गए। यह सूची बहुत लंबी है।

खेल
प्रमुख समाचार

तन्वी शर्मा ताइपे ओपन के फाइनल में पहुंची

नईदिल्ली। युवा भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने शनिवार को यहां चीनी ताइपे की हुआंग यु सुन पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में प्रवेश किया। पिछले साल के यूएस ओपन सुपर 300 में उपविजेता रही पंजाब की 17 वर्षीय खिलाड़ी तन्वी ने सेमीफाइनल में यु सुन को केवल 33 मिनट में 21-17, 21-11 से पराजित किया। यहां फाइनल मुकाबला दो भारतीय खिलाड़ियों के बीच होने की संभावना थी लेकिन महिला एकल के दूसरे सेमीफाइनल में उन्नति हुडा को वियतनाम की विश्व में नंबर 21 थूई लिन्ह गुयेन से 15-21 18-21 से हार का सामना करना पड़ा।

इस तरह से विश्व जूनियर चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता तन्वी रविवार को होने वाले फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी से भिड़ेंगी। तन्वी 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा थीं। उन्होंने पिछले दो वर्षों में काफी प्रगति की है। तन्वी ने 2025 में ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 और गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 में उपविजेता रहने के अलावा 2024 में बॉन इंटरनेशनल और 2025 में डेनमार्क चैलेंज जीता था। तन्वी ने शुरू से आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया तथा अपने तेज क्रॉस-कोर्ट स्मैश और पुश शॉट्स से हुआंग को बार-बार परेशान किया। पहले गेम में स्कोर 3-3 से बढ़कर 7-6 हो गया। तन्वी ने इसके बाद पूरे गेम में मामूली बढ़त बनाए रखी और 14-10 से 17-11 तक पहुंच गई। स्थानीय खिलाड़ी ने स्कोर को 15-17 तक कम कर दिया, जिसके बाद तन्वी ने आक्रामक खेल दिखाया और पहला गेम अपने नाम कर दिया। दूसरे गेम में हुआंग ने स्कोर 9-9 से बराबर कर दिया, लेकिन तन्वी इसके बाद हावी हो गई। उन्होंने बैक कोर्ट से सटीक शॉट लगाते हुए नेट पर चतुराई से ड्रॉप शॉट भी मारे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए से ज्यादा सस्ता

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने शनिवार (1 अगस्त) को दिल्ली और कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से ज़्यादा की कटौती की है। यह कदम पश्चिमी एशिया में संकट के कारण महीनों तक कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये की कटौती की गई है, जो तुरंत लागू हो गई है। इस कटौती के बाद, शनिवार से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,728 रुपये और कोलकाता में 2,872.50 रुपये होगी। हालांकि, सूत्रों के हवाले से बताया कि घरों में सप्लाई होने वाले 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 202 रुपये कम कर दी गई है।

आरबीआई की स्वैप स्कीम से बैंकों ने जुटाए विदेशी फंड

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई रियायती स्वैप सुविधा को देश और विदेश के निवेशकों के साथ-साथ बैंकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। आरबीआई के मुताबिक, 31 जुलाई तक इस स्कीम के जरिए बैंकों ने करीब 41 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा जुटा ली है। यह रकम मुख्य रूप से FCNR(B) डिपॉजिट, ओवरसीज फॉरेन करंसी बॉरोइंग (OFCBs) और एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECBs) के जरिए आई है। इन 41 अरब डॉलर में सबसे बड़ा योगदान FCNR(B) डिपॉजिट का रहा, जिससे 36.7 अरब डॉलर जुटाए गए। इसके अलावा OFCBs के जरिए 2.57 अरब डॉलर और ECBs के माध्यम से 1.5 अरब डॉलर का फंड मिला। खास बात यह है कि यह स्कीम शुरू होने के दो महीने से भी कम समय में 2013 का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।

जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ रु. पर पहुंचा

नईदिल्ली। सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जुलाई में 15.4 प्रतिशत बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया। घरेलू लेनदेन और आयात से अधिक कर संग्रह के कारण जीएसटी संग्रह बढ़ा है। शनिवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। पिछले वर्ष जुलाई में सकल जीएसटी संग्रह 1.83 लाख करोड़ रुपए रहा था। वहीं, जून 2026 में यह लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में कुल जीएसटी संग्रह 2,11,205 करोड़ रुपए रहा। आंकड़ों के अनुसार, जुलाई के दौरान केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) से 39,835 करोड़ रुपए, राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से 47,881 करोड़ रुपए और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से 1.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह हुआ।

हुंदै मोटर इंडिया की बिक्री जुलाई में 75,360 इकाई रही

नईदिल्ली। हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) की बिक्री जुलाई 2026 में 25.4 प्रतिशत बढ़कर 75, 360 इकाई रही। यह कंपनी की अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री है। एचएमआईएल ने जारी बयान में कहा कि घरेलू बाजार में भी बिक्री अब तक की सर्वाधिक 54,210 इकाई रही, जो पिछले वर्ष के इसी माह से 23.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। निर्यात 31.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ 21,150 इकाई रहा। कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं सीईओ तरुण गर्ग ने कहा, ''हमने नयी तिमाही की शुरुआत मजबूत प्रदर्शन के साथ की है। जुलाई में कुल 75,360 इकाई की बिक्री (घरेलू और निर्यात 25.4 प्रतिशत सालाना आधार पर) कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी मासिक बिक्री है, जो ग्राहकों के हुंदै ब्रांड पर बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।''

रूस प्रतिबंध बिल ने भारत-अमेरिका संबंधों में नई परेशानी खड़ी कर दी

निर्मला गणपति

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे अमेरिका के एक तेजी से आगे बढ़ते बिल ने रिश्ते में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ दी है। इस बिल में रूस से तेल खरीदने पर भारत समेत दूसरे देशों पर 100 परसेंट टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है।

अमेरिका सीनेट ने लिंडसे ओ। ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को फास्ट-ट्रैक करने के लिए वोट किया, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रशियन तेल के पांच बड़े खरीदारों, यानी इंडिया, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की इजाजत मिल जाएगी।

इसके अलावा इसमें अमेरिका में रूस के इंपोर्ट पर 500 परसेंट टैरिफ लगाया गया है और ईरान के खिलाफ बैन भी शामिल हैं। सरकार ने अभी तक इस पर कोई राय नहीं दी है, और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार अंदाज़ों वाली रिपोर्ट पर कमेंट नहीं करती है।

यह बिल ऐसे समय में आया है जब इंडिया-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता अधर में लटका हुआ है, जिससे ट्रेड संबंधों के आगे के रास्ते को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। भारत ने ईरान के साथ बढ़ते विवाद और होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई रूट में रुकावटों के बीच रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है।

मई 2026 में रूस से भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कुल इंपोर्ट का 40 परसेंट पार कर गया। अगर यह बिल कानून बन जाता है और ईरान का झगड़ा नहीं सुलझता है, तो इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ट्रेड एक्सपर्ट और पूर्व प्रोफेसर बिस्वजीत धर ने

कहा, रूसी तेल पर हमारी डिपेंडेंस बढ़ गई है, और इसलिए यह 100 परसेंट टैरिफ हम पर बहुत बुरा असर डालेगा। अगर हम अमेरिका या वेनेजुएला से इंपोर्ट करने लगते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम महंगाई को कैसे मैनेज करेंगे? इसका एक बड़ा असर होगा। यह सिर्फ एक परेशानी से कहीं ज़्यादा होने वाला है। ट्रंप सच में इस बिल को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय इकॉनमी को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स में मंजूरी मिलने से लेकर एग्जीक्यूटिव मंजूरी मिलने तक, इस कानून को अभी कुछ स्टेप्स से गुजरना है। लेकिन कम से कम एक अमेरिकी सीनेटर, जॉन थ्यून को उम्मीद है कि यह बिल अगले कुछ दिनों में पास हो जाएगा।

यह इस देश और हमारे नेशनल सिक्योरिटी हितों के लिए एक जरूरी बिल है, और मुझे उम्मीद है कि हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं और आखिरकार इसे पास कर सकते हैं, अगले कुछ दिनों में इसे यहीं खत्म कर सकते हैं। यह बिल अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा घोषित टैरिफ की सीरीज में सबसे नया है, जो भारतीय हितों को टारगेट करता है और आर्थिक व्यापार संबंधों को मुश्किल बनाता है। ट्रंप ने हाल ही में एक फेज़्ड जेनेरिक दवा टैरिफ प्लान की घोषणा की, जिसके तहत अमेरिका अगस्त 2028 से 100 परसेंट टैरिफ़ लगाना शुरू करेगा, जो अगस्त 2029 में बढ़कर 200 परसेंट हो जाएगा ताकि कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ले जाने का समय मिल सके।

इससे फार्मा सेक्टर पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है, जो अमेरिका की जेनेरिक दवाओं की लगभग 40 परसेंट डिमांड पूरी करता है। अमेरिका ने ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत भारत पर 10 परसेंट टैरिफ भी लगाया है, जो उन 60 देशों में से है जिन्हें जबरदस्ती मजदूरी वाले इम्पोर्ट पर रोक लगाने में नाकाम रहने के कारण टैरिफ का सामना करना पड़ा है। अब सवाल यह है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता के पहले हिस्से का क्या होगा, जिसकी घोषणा पहली बार 2025 में की गई थी। इन टैरिफ ने पहले हिस्से को फाइनल करने में मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि भारत को इस बात की चिंता है कि दूसरे देशों को बेहतर टैरिफ डील मिलेगी, जिससे अमेरिका को भारतीय एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा।

लखपति दीदी सम्मेलन में आएंगे प्रधानमंत्री मोदी

केन्द्र ने दिया हर सहयोग का भरोसा: सीएम साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हम लोग तीन दिनों के प्रवास पर दिल्ली गए थे. सीएम ने कहा कि दिल्ली प्रवास बहुत ही अच्छा रहा. पहले दिन माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम लोगों ने मुलाकात की. हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी हमारे साथ थे. इस दौरे पर बस्तर के लोग, पद्मश्री और बस्तर पंडुम के विजेता भी थे. इनके अलावा मांझी, चालकी जिनका बस्तर दशहरा को संचालित करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है. सबका पहली बार राष्ट्रपति भवन में जाना हुआ था. इतने बड़े जन जातीय समाज के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत हुआ. महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने कर कमल से अंग वस्त्र पहनाकर बस्तर के लोगों का स्वागत किया. राष्ट्रपति भवन के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित भी किया. दोपहर का भोजन भी राष्ट्रपति भवन में हुआ और सब का सौभाग्य की उन्होंने भोजन परोसा.

पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई. बस्तर के नक्सल मुक्त गांवों का विद्युतीकरण होना है. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास गया हुआ है. इसकी स्वीकृति के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया है. राजनांदगांव में प्रस्तावित जो यूरिया संयंत्र है उसके लिए हम लोगों ने जमीन भी प्रदान कर दिया है. 421 एकड़ जमीन है. इसकी स्वीकृति के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी आग्रह किए हैं. हमारे प्रदेश में आयुर्वेद का एम्स खोलने का भी आग्रह हमने प्रधानमंत्री जी से की है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्नेह के साथ सब बातों को सुना है और कहा है कि यह काम हमारे प्रदेश में होंगे. आने वाले समय में यहां पर लखपति दीदियों का बड़ा महा सम्मेलन करेंगे उसका आमंत्रण प्रधानमंत्री जी को दिए हैं. उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया है. वे इस सम्मेलन में आएंगे.

केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा

सीएम ने कहा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि भवन में मुलाकात हुई है. उनके पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है तो हम लोगों ने उनसे बस्तर को लेकर निवेदन किया है. हमारे बस्तर क्षेत्र में बसाहट के 10 किलोमीटर की परिधि को एक यूनिट मानकर वहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति दी जाए. सार्वजनिक वितरण तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है. उनसे आग्रह किए हैं कि प्रत्येक महीना 5 लाख मीट्रिक टन चावल यहां से लें ताकि जल्दी-जल्दी यहां पर लोगों को मदद मिले. केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम से भी मुलाकात हुई है।

महानदी जल विवाद का होगा समाधान

सीएम ने कहा कि महानदी जल बंटवारे का मामला है. जो कई वर्षों से ओडिशा के साथ विवाद चल रहा था. बड़ा गौरव का विषय है कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है उसमें लगातार प्रयास हो रहा है. अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी के साथ हमारी मीटिंग हुई.केन्द्रीय जल आयोग को 3 महीने में प्रदेश के हित और अधिकार को देखते हुए इसका निर्णय करने को कहा गया है. अब आने वाले 3 महीने से जल बंटवारे का भी समाधान हो जाएगा।

रेल मंत्री से हुई चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भी विषय में चर्चा हुई है. खुशी का विषय है कि कई सौगात हम लोगों को मिलने वाला है. सीएम ने कहा कि उसमें एक कटघोरा से डोंगरगढ़ नया रेलवे लाइन परियोजना है. यह 295 किलोमीटर लंबा है. अब इस लाइन के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है. इस रेल लाइन के बनने से कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा, बैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक रेल लाइन जाएगी. इससे कई हमारे ऐसे जिले जो रेल सेवा से नहीं जुड़े हैं वह रेल सेवा से जुड़ जाएंगे. वहां भी अब रेल पहुंच सकेगी. छत्तीसगढ़ के लिए अंबिकापुर धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा और अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन की भी स्वीकृति का हमने रेल मंत्री जी से आग्रह किया है. रावघाट जगदलपुर रेल लाइन की स्वीकृति पहले ही मिली है।

स्मार्ट मीटर और सोलर संयंत्र से नहीं बढ़ता बिजली बिल, फैक्ट चेक में हुई पुष्टि

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर संयंत्र लगाने के बाद भी एक लाख 11 हजार रुपए का बिजली बिल आने की शिकायत की छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने उच्चस्तरीय जांच कराई। जांच में पाया गया कि जिस उपभोक्ता ने शिकायत की थी, उसके नाम से न तो सोलर संयंत्र स्थापित है और न ही उसके घर स्मार्ट मीटर लगा है। संबंधित विद्युत कनेक्शन पर पुराना मीटर ही लगा हुआ है। वास्तविकता यह है कि उपभोक्ता के घर में विद्युत उपकरण अधिक होने के कारण बिजली की खपत भी अधिक है तथा उसने पिछले पांच माह से बिजली बिल जमा नहीं किया है। पावर कंपनी की जांच (फैक्ट चेक) में यह स्पष्ट हुआ कि स्मार्ट मीटर अथवा सोलर संयंत्र से बिजली बिल नहीं बढ़ता है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कवर्धा जिले के बोड़ला विकासखंड के ग्राम सिल्हाटी निवासी उपभोक्ता श्री तिलक राम चंद्रवंशी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई। उन्होंने शिकायत की थी कि सोलर संयंत्र लगाने के बाद भी उनका बिजली बिल ?1 लाख 11 हजार 650 आया है। इस संबंध में कुछ मीडिया माध्यमों में समाचार प्रकाशित हुए, जिनमें विभाग का पक्ष शामिल नहीं था।

मामले की जांच के लिए पंडरिया के कार्यपालन अभियंता श्री के.के. झा एवं बोड़ला उपसंभाग के सहायक अभियंता श्री सुनील कुमार कंवर को जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच दल ने मौके पर पहुंचकर शिकायत का परीक्षण किया तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के अनुसार श्री तिलक राम चंद्रवंशी के बी.पी. क्रमांक 1002557014 पर पुराना मीटर लगा हुआ है। उक्त कनेक्शन पर न तो स्मार्ट मीटर लगाया गया है और न ही कोई रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित है।

जांच में यह भी पाया गया कि श्री तिलक राम चंद्रवंशी के तीन भाइयों का संयुक्त परिवार है, जिसमें पूर्व से एक ही विद्युत कनेक्शन से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। पिछले तीन माह से इस परिसर में 8 किलोवाट से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया जा रहा है।

कुलगाम आतंकी हमला, सीएम साय ने किया मुआवजे का ऐलान

रायपुर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों की मौत हुई है. सीएम साय ने सक्ती जिले के निवासी दीपक रात्रे और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के निवासी भूपेंद्र भैना के निधन पर शोक जताया है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस दु:ख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार दोनों परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है. उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार की ओर से दोनों दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

मुख्यमंत्री साय ने इस जघन्य और अमानवीय आतंकी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के विरुद्ध अपराध है और ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्त की जाएगी, जो परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा-विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है.

कुलगाम में आतंकी हमला शुक्रवार की देर शाम को किया गया. यहां दक्षिण कश्मीर के केलम इलाके में स्थित ईंट भट्ठे पर मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया. आतंकियों ने नाम पूछकर मजदूरों को गोली मारी. इस हमले में दीपक कुमार और भूपिंदर नाम के दो मजदूर घायल हो गए. दीपक ने मौके पर दम तोड़ दिया जबकि भूपिंदर ने एसकेआईएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

कुलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों से गृहमंत्री शर्मा ने की बात

जम्मू-कश्मीर। कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दीपक रात्रे एवं भूपेन्द्र की निर्मम हत्या की सूचना मिलते ही उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान तत्काल दोनों दिवंगतों के परिजनों से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने शोकाकुल परिवारों को ढांढस बंधाते हुए इस कठिन समय में राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। शर्मा ने अधिकारियों को भी आवश्यक समन्वय एवं हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घटना ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक में डाल दिया है।उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध है। आतंकवाद के ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और इस नृशंस हमले में शामिल आतंकियों को उनके अपराध की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि आतंकियों को उनके कृत्य का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और इस हमले का बदला अवश्य लिया जाएगा।शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा दोनों पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह संवेदनशील निर्णय शोक संतप्त परिवारों को कठिन समय में संबल प्रदान करेगा तथा राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। वे पीड़ित परिवारों के साथ रहकर उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने तथा स्थानीय प्रशासन के साथ आवश्यक समन्वय सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे वनमंत्री केदार कश्यप

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर जिले के पालकी गांव पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिले और उनका हालचाल जाना। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली तथा हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। मंत्री श्री कश्यप ने प्रभावित परिवारों को राहत सहायता राशि के चेक और कंबलों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय प्रभावित लोगों तक त्वरित राहत पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राहत सामग्री और जरूरी सहायता समय पर हर परिवार तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। सरकार का लक्ष्य राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाकर प्रभावित लोगों के जीवन को जल्द से जल्द सामान्य बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जाएं। जिन परिवारों को अतिरिक्त सहायता की जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाए।

संकट की घड़ी में सरकार साथ वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रत्येक जरूरतमंद तक राहत और सहायता पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार हर प्रभावित नागरिक को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य आदेश भूपेश सरकार ने दिया

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने स्मार्ट मीटर मुद्दे को लेकर कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही है और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो आंदोलन की राह पकड़ रही है, वह पूरी तरह उसका ढोंग और घड़ियाली आँसू बहाना है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने शनिवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछली भूपेश बघेल सरकार ने ही प्रदेश पर स्मार्ट मीटर का बोझ थोपा था। अब कांग्रेस नेताओं और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को वर्तमान सरकार से सवाल पूछने के बजाय अपनी पूर्ववर्ती भूपेश सरकार और उनकी कैबिनेट से सवाल करना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया वर्ष 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। शुरुआत में यह तय किया गया था कि स्मार्ट मीटर केवल अमृत सिटी, औद्योगिक, व्यावसायिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में ही लगाए जाएंगे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नियमों को दरकिनार करते हुए प्रदेश के आम घरेलू उपभोक्ताओं पर भी इसे जबरन थोप दिया।

आदिवासी सम्मान कांग्रेस को क्यों चुभ रहा है: कश्यप

रायपुर। वनमंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बस्तर पंडुम और राष्ट्रपति भवन में बस्तर के आदिवासी प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से हुई भेंट को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक हताशा नहीं, बल्कि बस्तर के जनजातीय समाज, उसकी संस्कृति, परंपराओं और अस्मिता का खुला अपमान है। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बस्तर की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और आदिवासी गौरव का महापर्व है। जिस आयोजन ने बस्तर के लोक कलाकारों, मांझी-चालकी व्यवस्था और जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाया, उसी पर सवाल उठाना बताता है कि कांग्रेस आदिवासी समाज के सम्मान को भी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन में बस्तर के आदिवासी प्रतिनिधियों की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से हुई ऐतिहासिक भेंट का भी उपहास उड़ाने का प्रयास किया है। आज़ादी के दशकों बाद पहली बार बस्तर के पारंपरिक वेशभूषा में सजे जनजातीय प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया, उनसे आत्मीय संवाद हुआ।

बस्तर पंडुम के नाम पर सरकार ने भ्रष्टाचार किया : दीपक बैज

रायपुर। पिछले दिनों सरकार ने बस्तर पंडुम से जुड़े आदिवासियों को दिल्ली घुमाने ले गयी तथा राष्ट्रपति से मुलाकात भी कराया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर पंडुम आदिवासियों के संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा एवं संस्कृति त्यौहार है, यह सरकार का कोई आयोजन नहीं है। सरकार ने इसे अपने आत्म प्रचार का माध्यम बनाने की कोशिश किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आदिवासियों को राष्ट्रपति से मिलाये दिल्ली, मुम्बई, विदेश घुमाने ले जाये, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या इससे आदिवासी वर्ग के युवाओं को नौकरी मिल जाएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के संकट दूर हो जाएंगे? बस्तर पंडुम के नाम से सरकार ने भारी भ्रष्टाचार किया है। राष्ट्रपति, केंद्रीय गृहमंत्री के आगमन पर टेंट, कुर्सी, पंडाल के आदि लगाने के नाम पर 6 करोड़ 14 लाख से अधिक गड़बड़ी की गई, जो पैसा दिखावे में खर्च किया गया, उसको आदिवासियों की बेहतरी पर खर्च होना था। 6.14 करोड़ में तो पिछली बारिश से टुटे दर्जनों पुल, पुलिया, सड़क बन जाते, जितना खर्चा टेंट, कुर्सी, आदि पर खर्च किया, उतने में तो सिमेंट का पक्का डोम बना जाता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार सिर्फ आदिवासियों को धोखा दे रही है।

नोटिस और पोस्टर-वार के खेल से बेनकाब हुआ कांग्रेस

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर मचे राजनीतिक घमासान, बढ़ती पद लोलुपता और अंतर्कलह पर तीखा तंज कसा है। %बैज बनाम पटेल% की जंग पर हमला बोलते हुए श्री ठोकने ने कहा कि सत्ता जाते ही कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है और अब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के भीतर खुलकर 'पोस्टर वार' और सिर-फुटौव्वल शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने कहा कि पूर्व मंत्री उमेश पटेल को पीसीसी चीफ बनाने की मांग उठने के बाद जिस तरह से पूर्व जिलाध्यक्ष अरुण मालाकार को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में सच बोलने वालों का दमन किया जा रहा है। खाबो लाठी, जाबो जेल, हमर नेता उमेश पटेल जैसे नारों के साथ सोशल मीडिया पर जारी यह जंग सिर्फ कुछ समर्थकों की नारेबाजी नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और उमेश पटेल के खेमों के बीच छिड़ी खुली राजनीतिक लड़ाई है। रायगढ़, बस्तर, रायपुर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह लामबंदी दर्शाती है कि कांग्रेस के भीतर डेढ़ दशक बाद कुर्सी के लिए ऐसा घमासान मचा है, जो अब छिपाए नहीं छिप रहा। एक तरफ बैज अपनी कुर्सी बचाने के लिए नोटिस की लाठी चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल समर्थक नेता इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।

वित्त मंत्री चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदक विजेता नीरज व यशवीर को दी बधाई

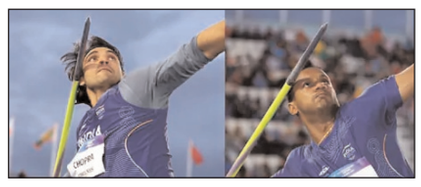

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा तथा कांस्य पदक जीतने वाले यशवीर सिंह को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन, कठिन परिश्रम और अटूट समर्पण के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। उनकी उपलब्धि प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह का उत्कृष्ट प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स की बढ़ती शक्ति और देश के खिलाड़ियों की विश्वस्तरीय क्षमता का प्रमाण है। समस्त देशवासियों को दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने नीरज चोपड़ा एवं यशवीर सिंह को पुन: हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य तथा आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करने की शुभकामनाएं दीं।

प्रेमचंद जयंती पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में बौद्धिक विमर्श इकाई का गठन

सत्यता और संतुलन ही भाषा की वास्तविक शुचिता: कुलपति दयाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के युगद्रष्टा मुंशी प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई के अवसर पर एक ऐतिहासिक पहल की गई। इस पावन अवसर पर विश्वविद्यालय में बौद्धिक विमर्श इकाई की स्थापना की गई, जिसके तहत सार्वजनिक जीवन में भाषा की शुचिता विषय पर एक विशेष राष्ट्रीय विमर्श आयोजित हुआ।

आम आदमी की सहज-सरल बोली को साहित्य के उच्च शिखर पर स्थापित किया इस अवसर पर कुलपति प्रो. डॉ. मनोज दयाल ने मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक एवं पत्रकारिता योगदान को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने अपनी धारदार लेखनी से समाज की विसंगतियों पर करारा प्रहार किया और आम आदमी की सहज-सरल बोली को साहित्य के उच्च शिखर पर स्थापित किया। आज के दौर में भाषा की शुचिता का दायरा केवल व्याकरणिक शुद्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सत्यता, वैचारिक संतुलन और वस्तुनिष्ठता का समाहित होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में संवाद का सकारात्मक प्रयोग समाज को जोड़ता है, जबकि मर्यादाहीन और कलुषित भाषा सामाजिक विभाजन को जन्म देती है।

डिजिटल युग में संवाद की मर्यादा सबसे बड़ी चुनौती

कुलसचिव श्री सुनील शर्मा ने कहा कि सफल संवाद वही है जो श्रोता की समझ और गरिमा को ध्यान में रखकर किया जाए। सार्वजनिक जीवन में हमारी भाषा का स्तर ही हमारे व्यक्तित्व और विचारों का दर्पण होता है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्यों ने रेखांकित किया कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की अति-सक्रियता के बीच भाषा की मर्यादा, संयम और संतुलन बनाए रखना पत्रकारिता और समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

नियमित रूप से होंगे समकालीन विषयों पर मंथन

विश्वविद्यालय में नवगठित बौद्धिक विमर्श इकाई के माध्यम से अब नियमित रूप से ज्वलंत व समकालीन विषयों पर परिचर्चाएँ आयोजित की जाएँगी, जिससे विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के बीच वैचारिक आदान-प्रदान की संस्कृति और मजबूत हो सके। इस अवसर पर डॉ. शैलेंद्र खंडेलवाल, डॉ. आशुतोष मंडावी, डॉ. नृपेंद्र शर्मा एवं डॉ. राजेंद्र मोहंती, पत्रकारिता विभागाध्यक्ष श्री पंकज नयन पांडेय उपस्थित थे।

पावर कंपनी से मुख्य अभियंता साव एवं देवांगन समेत 7 अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ में आयोजित सेवानिवृत्ति विदाई समारोह में दो मुख्य अभियंताओं सहित सात अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एस.के. कटियार एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में मुख्य अभियंता राजेन्द्र कुमार साव एवं आशुतोष देवांगन सहित सात अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। प्रबंध निदेशक श्री एस.के. कटियार ने सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य अभियंता राजेन्द्र कुमार साव एवं आशुतोष देवांगन ने अपने दीर्घ सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए कंपनी प्रबंधन, वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहकर्मियों से प्राप्त सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।

समारोह में कार्यपालक निदेशक एम.एस. कंवर, सी.एल. नेताम, संदीप मोदी एवं संजय शुक्ला सहित मुख्य अभियंता गिरीश गुप्ता, सुभाष शर्मा, एच.एन. कोसरिया, रोहित डहरवाल उपस्थित थे।इसी प्रकार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा सेवा भवन में आयोजित समारोह में पाँच अधिकारी एवं कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.